भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस शोधपत्र

अफगानिस्तान "संकट"

और

तालिबान की शासन-प्रणाली

डॉ. अन्वेषा घोष

भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस शोधपत्र

अफगानिस्तान "संकट"

और

तालिबान की शासन-प्रणाली

डॉ. अन्वेषा घोष

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य का सृजन करना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान व चिंतन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। संस्था नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित कई बौद्धिक गतिविधियां आयोजित करती है और कई प्रकार के प्रकाशन भी प्रकाशित करती है। संस्था के पास अच्छे संग्रह वाला एक पुस्तकालय है, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह त्रैमासिक इंडिया पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर ज्ञान को बढ़ावा देने तथा आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद की भारत में प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंकों तथा विश्वविद्यालयों के साथ भी भागीदारी है।

अफगानिस्तान "संकट" और तालिबान की शासन-प्रणाली

सर्वप्रथम विश्व मामलों की भारतीय परिषद में जनवरी 2023 में प्रकाशित

आईएसबीएन: 978-93-83445-71-4

सभी अधिकार आरक्षित हैं। कॉपीराइट धारक की लिखित अनुमति के बिना, इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा किसी भी प्रारूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा, पुन: प्रस्तुत या किसी पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में उद्धृत तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेषतः लेखकों की है और उनकी व्याख्या विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को व्यक्त नहीं करती है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद,

सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड नई दिल्ली 110001, भारत

टेलीफोन: +91-11-2331 7242 | फैक्स: +91-11-2332 2710

www.icwa.in

अंतर्वस्तु

सार-संक्षेप . . . .

प्रस्तावना . . . .

1. अफगानिस्तान "संकट": ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में राष्ट्र के गठन पर विवाद . . . . .
2. अमेरिका का हटना एवं अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य का विघटन . . . .
3. अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी . . . .
4. अफगानिस्तान के सामने मुख्य चुनौतियां . . . .
5. इतिहास से सबक जो तालिबान शासन-प्रणाली के पक्ष में हो सकते हैं . . . .
6. संभावित परिदृश्य: अफगानिस्तान की आगे की राह क्या हो सकती है? . . . .

निष्कर्ष . . . .

सार-संक्षेप

विगत कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में कई बार शासन परिवर्तन हुए हैं; और ऐसी घटनाओं ने देश में बार-बार राजनीतिक 'संकट' पैदा हुआ है। 2021 में अफ़ग़ान गणराज्य के विघटन के तत्काल पश्चात ऐसा दोबार हुआ। बीस वर्ष तक उग्रवाद छेड़ने के बाद, तालिबान 15 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान में सत्ता में लौट आया। इसके बाद के घटनाक्रमों से अफगानिस्तान में एक गंभीर, बहुआयामी एवं परस्पर-संबंधित मानवीय, आर्थिक तथा राजनीतिक संकट की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान में हालिया शासन परिवर्तन तथा संकट को देखते हुए, सप्रू हाउस के इस शोधपत्र में अफगानिस्तान में राज्य गठन के पहले के प्रयासों पर चर्चा की गई है तथा इस प्रक्रिया में शामिल उन प्रमुख ताकतों पर चर्चा की गई है जिन्होंने अतीत में यहां पिछली सदी में शासन परिवर्तनों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके पश्चात शोधपत्र में 2001 के बाद के अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के नेतृत्व वाले दौर पर और उन प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है जिसके कारण अगस्त 2021 में अफगान गणराज्य का विघटन हुआ। तीसरा और चौथा खंड क्रमशः वर्तमान तालिबान शासन और अफगानिस्तान द्वारा सामना की जाने वाली तात्कालिक चुनौतियों पर केंद्रित है। इसके बाद शोधपत्र इस बात को समझने हेतु इतिहास में झांकने की कोशिश करता है कि तालिबान का दूसरा कार्यकाल कितना सुरक्षित हो सकता है। इसके अंत में अफगानिस्तान के लिए तीन संभावित मध्यम-से-दीर्घावधि परिदृश्यों पर चर्चा की गई है, जो अगले कुछ वर्षों में सामने आ सकते हैं।

मुख्य शब्द : अफगानिस्तान, सियाई-फॉरमाइयन, तालिबान, अमेरिका का हटना, संकट, संभावित परिदृश्य।

प्रस्तावना

20 साल तक उग्रवाद का रास्ता अपनाने के बाद, तालिबान 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में सत्ता में लौट आया। अमेरिकी सेना ने तय समय से एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को अफगानिस्तान में 20 सालों से मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप का प्रमुख सहयोगी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने भी इसी समय के आसपास अफगानिस्तान से हटने का फैसला किया। चार दशकों से अधिक युद्ध एवं अस्थिरता से तबाह हो चुके अफ़गानिस्तान में पश्चिमी देशों की सैनिकों की वापसी से, जैसा कि बीबीसी पत्रकार लिसे डौकेट ने कहा था - "उथल-पुथल और असमंजस की स्थिति" आ गई।[1] पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार अफगानिस्तान को "आवश्यक युद्ध" बताया था, ऐसा युद्ध जिसे अमेरिका को हर हाल में जीतना था। अमेरिका की अपमानजनक हार के बावजूद राष्ट्रपति जो बिडेन ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी के इस सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने हेतु अमेरिका और नाटो बलों को वापस बुलाना सही निर्णय था। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकियों को उन लोगों की ओर से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए और मरना नहीं चाहिए जिनके पास स्वयं ऐसा करने की इच्छा नहीं है। यद्यपि अफगानिस्तान में अमेरिका का युद्ध अमेरिकी सैनिकों के हटते ही समाप्त हो गया

अफगानिस्तान का इतिहास शासन परिवर्तन के कई उदाहरणों से भरा हुआ है, और इन घटनाओं से देश में बार-बार राजनीतिक "संकट" उत्पन्न हुआ है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्ज़ा करने के तत्काल बाद यही फिर से दोहराया गया।

था, लेकिन इस बात को लेकर बहुत कम स्पष्टता थी कि अफगान राष्ट्र या कुछ प्रमुख समर्थकों, संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान का भविष्य क्या होगा। उस समय, ऐसा लग रहा था कि वाशिंगटन की विदेश नीति अंततः इस विचार से प्रभावित थी कि ग्रेटर मिडिल ईस्ट में न केवल काफी थकाऊ, महंगे युद्ध हैं - $6.4 ट्रिलियन और बढ़ते जा रहे हैं-बल्कि दुनिया में अमेरिका की स्थिति को भी कमजोर कर रहे हैं, विशेषतः अपने रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों, चीन व रूस की तुलना में।[2]

अफगानिस्तान का इतिहास शासन परिवर्तन के कई उदाहरणों से भरा हुआ है, और इन घटनाओं से देश में बार-बार राजनीतिक "संकट" उत्पन्न हुआ है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्ज़ा करने के तत्काल बाद यही फिर से दोहराया गया। इस्लामिक गणराज्य के विघटन और काबुल में तालिबान की वापसी के साथ ही चारों ओर अराजकता फैल गई थी। जल्द ही अफगानिस्तान छोड़ने की हताश कोशिश शुरू हो गई। अचानक हुए इन घटनाक्रमों से आम अफगानी नागरिक अपने भविष्य और उन लोगों के भविष्य को लेकर चिंतित और भयभीत हो गए जो पीछे

छूट जाएंगे। चूंकि दुनिया तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तानी नागरिकों के भविष्य से जुड़े सवाल का जवाब तलाश रही थी, वहां विरोध और बमबारी हुई - निराशा की भावना ने देश को घेर लिया। इन सबके बीच, अफगानिस्तान के नए शासकों ने "अंतरिम सरकार" पेश करने में कामयाबी हासिल की, जो 1990 के दशक के अंत में उनके क्रूर शासन की याद दिलाती हुई कार्रवाई मानी गई।

अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद, अफगान केंद्रीय बैंक में जमा अरबों डॉलर एवं अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता को तालिबान के हाथों में पड़ने से रोकने से रोक दिया गया था। इन घटनाक्रमों ने अफगानिस्तान में गंभीर, बहुआयामी और संबद्ध मानवीय, आर्थिक व राजनीतिक संकटों को जन्म दिया। हालांकि पिछले 1 साल के दौरान, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जुड़ने का प्रयास किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा नए शासन को "औपचारिक मान्यता" का इनाम तालिबान के हिस्से नहीं आया है। अफ़ग़ानिस्तान के भीतर और बाहर, दोनों ओर पर्यवेक्षक इस बात को लेकर आशंकित हैं कि देश यहाँ से किस दिशा में जाएगा। अफगान गणराज्य के विघटन के तत्काल बाद की अराजकता की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर चिंता पैदा कर दी क्योंकि वे अपने-अपने देशों पर अस्थिर अफगानिस्तान के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

अफगानिस्तान में हालिया शासन परिवर्तन तथा संकट को देखते हुए, सप्रू हाउस के इस शोधपत्र में अफगानिस्तान में राज्य गठन के पहले के प्रयासों पर चर्चा की गई है तथा इस प्रक्रिया में शामिल उन प्रमुख ताकतों पर चर्चा की गई है जिन्होंने अतीत में यहां पिछली सदी में शासन परिवर्तनों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके पश्चात शोधपत्र में 2001 के बाद के अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के नेतृत्व वाले दौर पर और उन प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है जिसके कारण अगस्त 2021 में अफगान गणराज्य का विघटन हुआ। तीसरा और चौथा खंड क्रमशः वर्तमान तालिबान शासन और अफगानिस्तान द्वारा सामना की जाने वाली तात्कालिक चुनौतियों पर केंद्रित है। इसके बाद शोधपत्र इस बात को समझने हेतु इतिहास में झांकने की कोशिश करता है कि तालिबान का दूसरा कार्यकाल कितना सुरक्षित हो सकता है। इसके अंत में अफगानिस्तान के लिए तीन संभावित मध्यम-से-दीर्घावधि परिदृश्यों पर चर्चा की गई है, जो अगले कुछ वर्षों में सामने आ सकते हैं।

1. अफगानिस्तान "संकट": ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में राष्ट्र के गठन पर विवाद

यह समझना मुश्किल है कि जब अफगानिस्तान में "संकट" पर चर्चा कब और कहां से शुरू करें: हम किस संकट की बात करें? इस संकट की शुरुआत कहां से हुई? क्या यह केवल राजनीतिक संकट था जो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन से शुरु हुआ था या इसके साथ अन्य प्रकार के संकट भी थे? क्या कोई सामान्य संबंध हैं जिससे हाल के और पहले के संकटों का एक-दूसरे से जुड़े होने का पता

चलता है? यह शोधपत्र इन सवालों में से कुछ का सवाल तलाशने का प्रयास करता है क्योंकि इसमें सबसे हालिया प्रयास पर चर्चा करने से पहले अफगानिस्तान में राज्य गठन के पिछले प्रयासों पर चर्चा की गई है। शोधपत्र का पहला खंड, इस विवरण के ज़रिए अफगानिस्तान में राज्य निर्माण के एक सदी पुराने संकट पर चर्चा करने की कोशिश करता है, लेकिन यह ऐसा केवल सबसे हालिया संकट को प्रासंगिक बनाने हेतु नहीं करता है। उन कारकों का विस्तृत विश्लेषण जिनके कारण अतीत में शासन परिवर्तन हुआ और उसके बाद संकट की प्रकृति इस शोधपत्र के दायरे से बाहर है।

अफगानिस्तान में संकट की प्रकृति चक्रीय रही है। पिछले सौ वर्षों के राजनीतिक बदलाव से ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान के संकट का एक पुराना घटक था और लगभग 10 या 20 वर्षों के अंतराल के भीतर यह बार-बार उभरता रहा। अफगानिस्तान के संदर्भ में राज्य निर्माण के प्रयासों पर

अफगानिस्तान में संकट की प्रकृति चक्रीय रही है। पिछले सौ वर्षों के राजनीतिक बदलाव से ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान के संकट का एक पुराना घटक था और लगभग 10 या 20 वर्षों के अंतराल के भीतर यह बार-बार उभरता रहा।

चर्चा करते हुए, वर्तमान खंड चार कारकों तथा ताकतों को चिन्हित करता है जो अफगानिस्तान में राज्य के गठन हेतु प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अर्थात्: (1) 1919 से संवैधानिक आंदोलन जिन्होंने इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर अफगान राज्य के निर्माण का प्रयास किया; (2) बाहरी शक्तियों द्वारा अपने प्रतिनिधि के ज़रिए राज्य बनाने और नियंत्रित करने का प्रयास; (3) 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक राज्य बनाने हेतु इस्लामवादियों के प्रयास; और (4) अफगान राज्य की पहचान को लेकर विभिन्न जातीय समूहों (विशेष रूप से, पश्तून और फ़ारसीवान, यानी फ़ारसी बोलने वाली आबादी) के संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएँ। यदि आप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक के अफगानिस्तान के इतिहास का अध्ययन करे, तो यह समझ जाएंगे कि उल्लेखित ताकतों ने - स्वतंत्र रूप से, साथ ही साथ एक-दूसरे के सहयोग से - पिछली शताब्दी के दौरान अफगान राज्य के प्रारूप और पहचान को प्रभावित करने की कोशिश की है।

राज्य गठन के प्रयास

अफगानिस्तान "दुर्बल राज्य सिंड्रोम" का एक "उत्कृष्ट उदाहरण" है।[3] ऐतिहासिक, भू-राजनीतिक, नृवंशविज्ञान, राजनीतिक एवं आर्थिक जैसे कई कारक, इसे कमजोर और संघर्ष-प्रवण राज्य बनाने हेतु जिम्मेदार हैं। एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक जगह पर स्थित, अफगानिस्तान ऐसे क्षेत्र में है जिससे हमेशा पड़ोसी देशों - उत्तर और पश्चिम में मध्य एशियाई गणराज्य, दक्षिण और पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, और आगे पूर्व में चीन और भारत के बीच प्रतियोगिता बढ़ी है। अफगान विदेशी

आक्रमणों से बचे नहीं रहे हैं। तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद से, उन पर अरबों, ईरानियों, तुर्कों और मंगोलों ने आक्रमण किया है। ज़ारिस्ट रूस और साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने अफ़गानों की बफर भूमि पर नियंत्रण के लिए कई "तरीके" आजमाए, और बाद में यह देश शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता का गवाह बना। अपनी भू-राजनीतिक स्थिति के अलावा, बीहड़ स्थलाकृति इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग देश बनाता है, लोगों व राज्य के बीच की दूरी को बढ़ाती है और कुछ हद तक आर्थिक विकास की कमी हेतु जिम्मेदार है। अफगानिस्तान की आबादी भी जातीय, भाषाई, सांप्रदायिक, आदिवासी व नस्लीय सीमाओं के साथ गहरे और बहुआयामी दरारों से विभाजित है। अफगान भी आपस में शक्ति संघर्ष के आदी रहे हैं और बड़े पैमाने पर उन कट्टरपंथी सुधारों का विरोध किया है, जो उन्हें लगा कि उनकी परंपराओं और विश्वास प्रणालियों के अनुरूप नहीं है। इन सभी कारकों की वजह से अफगानिस्तान एक "कमजोर राज्य" बना रहा, जिसकी वजह से हाल के दिनों में और अतीत में कई "संकट" देखे गए हैं।

राजवंशीय नियमों और साम्राज्यों के रूप में पूर्व-आधुनिक राज्य या प्राधिकरण सदियों से इस क्षेत्र में मौजूद हैं। उपनिवेशवाद की शुरुआत के बाद, इस सामान्य सभ्यतागत क्षेत्र की राजनीतिक संरचना और सांस्कृतिक स्थिति यूरो-केंद्रित राष्ट्रीय राज्य प्रणाली और राष्ट्रवाद की विचारधारा के लागू होने से मौलिक रूप से बदल गई।[4] 1880 के दशक में अमीर अब्दुर्रहमान (बराकजई पश्तून जनजाति से) के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता और विशेषतः अमीर को ब्रिटिश साम्राज्य से प्राप्त समर्थन के परिणामस्वरूप समकालीन अफगानिस्तान का गठन "आधुनिक राज्य" के रूप में हुआ था।[5] याकूब इब्राहिमी जैसे अफगान विद्वानों ने तर्क दिया है कि औपनिवेशिक शक्तियों ने पश्तून अभिजात वर्ग को सशक्त बनाया और उन्हें जातीय रूप से विविध एवं विषम समाज पर शासन करने हेतु वैचारिक, संगठनात्मक, वित्तीय और अन्य संसाधन प्रदान किए। पश्तून-प्रभुत्व वाले अफगान राज्य ने देश के अन्य जातीय समूहों को अधीन कर दिया और एक आधिकारिक उपदेश का निर्माण किया, और उस उपदेश ने औपनिवेशिक ज्ञान के साथ मिलकर पश्तून-वर्चस्व वाले राज्य के गठन को स्वाभाविक एवं ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया।

अफगानिस्तान में राज्य गठन के पहले के प्रयासों पर बात करते हुए, डूरंड रेखा के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर, इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन एवं जारिस्ट रूस के बीच औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के "ग्रेट गेम" में देखी जा सकती है। अफगानिस्तान, ऐतिहासिक रूप से विभिन्न फ़ारसी, मध्य एशियाई और दक्षिण एशियाई राज्यों के बीच चौराहे पर स्थित, औपनिवेशिक विस्तार के इस ग्रेट गेम के मुख्य मंच के रूप में उभरा। 1893 में चित्रित डूरंड रेखा ने विभिन्न पश्तून जनजातियों की मातृभूमि को विभाजित करने की प्रक्रिया में हिंदू कुश को अफगान और ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया। हालांकि पश्तून अफगानिस्तान में प्रमुख जातीय समूह थे, लेकिन पाकिस्तान - ऐसा देश जो 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद उभरा - में भी पश्तून बड़ी संख्या में थे।

सीमा-विभाजन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से हुई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि सीमा क्षेत्र में समुदायों को विभाजित करेगी या हिंदू कुश की सांस्थिति से इस सीमा के वास्तविक प्रवर्तन की

अनुमति मिलेगी या नहीं। चीजों और बदतर तब हो गई, जब अफगान और ब्रिटिश वार्ताकारों ने अलग-अलग नक्शों का इस्तेमाल किया जो अपर्याप्त आकार के थे, जिससे सीमा (सैद्धांतिक रूप से)

डूरंड रेखा को लेकर चर्चा अंततः नैतिक और व्यावहारिक चिंताओं को उठाती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों से सलाह के बिना सीमा खींची गई थी, और शुरू से ही आदिवासी समुदायों के मनमाने विभाजन ने राजनीतिक सीमा के रूप में डूरंड रेखा को सामाजिक रूप से अवैध बना दिया।

कहां स्थित थी, इसे लेकर अस्पष्टता पैदा हुई।[6] डूरंड रेखा को लेकर चर्चा अंततः नैतिक और व्यावहारिक चिंताओं को उठाती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों से सलाह के बिना सीमा खींची गई थी, और शुरू से ही आदिवासी समुदायों के मनमाने विभाजन ने राजनीतिक सीमा के रूप में डूरंड रेखा को सामाजिक रूप से अवैध बना दिया।

सीमा कहाँ स्थित है, इसको लेकर मानचित्रण प्रक्रिया से अस्पष्टता पैदा हो गई। अधिकांश पश्तूनों ने इस सीमा को मनमाना एवं जबरदस्ती माना है, और डूरंड रेखा इस्लामाबाद तथा काबुल के संबंधों में सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभरी है। डूरंड रेखा का आरेखण अंततः दक्षिण एशिया में रूसी विस्तारवाद को रोकने हेतु हिंदू कुश पर नियंत्रण बढ़ाने के ब्रिटिश सरकार का प्रयास माना जाता है। चर्चा का एक महत्वपूर्ण घटक और डूरंड व अब्दुर रहमान खान के बीच अंतिम समझौता डूरंड समझौते के औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता हैं। अफगान पक्ष में, अब्दुर रहमान खान ने अमीर की भूमिका में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाद के दशकों में, यह तर्क दिया गया है कि डुरंड रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं माना जा सकता है क्योंकि समझौता व्यक्तिगत रूप से आमिर द्वारा किया गया था, न कि

राष्ट्रीय राज्य के लिए प्रारंभिक नींव तब रखी गई थी जब राजा अमानुल्लाह के नेतृत्व में 1919 में एंग्लो-अफगान संधि के बाद अफगानिस्तान ने ब्रिटिश संरक्षित स्थिति को त्याग कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

अफगानिस्तान के अमीरात द्वारा।[7] हालांकि, पाकिस्तान ने जोर देकर कहा है कि डूरंड रेखा दोनों देशों को अलग करने वाली कानूनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसे अफ़गानिस्तान (तालिबान सहित) के कई शासनों ने खारिज कर दिया है।

यद्यपि 19वीं शताब्दी के मध्य में एक आधुनिक राज्य का उदय एवं विकास शुरू हुआ, लेकिन इस राज्य की कोई राष्ट्रीय विशेषता नहीं थी। इस राष्ट्रीय राज्य की प्रारंभिक नींव तब रखी गई थी जब राजा अमानुल्लाह के नेतृत्व में 1919 में एंग्लो-अफगान संधि के बाद अफगानिस्तान ने ब्रिटिश संरक्षित स्थिति को त्याग कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उनका एक प्रमुख कार्यक्रम देश का आधुनिकीकरण था। अफ़गानिस्तान में आधुनिक राज्य के निर्माण के प्रमुख प्रयासों में से एक

अमानुल्लाह खान के दौरान होने वाला संवैधानिक आंदोलन माना गया था। अमानुल्ला खान ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार शुरू किए और 1923 में, राज्य में इस्लामी दुनिया के सबसे पुराने संविधानों को लागू किया। राजा अमानुल्लाह यूरोपीय देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास से काफी प्रभावित थे, और उन्होंने अफगानिस्तान को आधुनिक राज्य बनाने की कोशिश की और यूरोपीय विकास मॉडल का अनुकरण करके उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की जिसमें महिलाओं की पूर्ण स्वतंत्रता, मोनोगैमी की शुरुआत, पुरुष-महिला दोनों की अनिवार्य शिक्षा और धर्म को राजनीति एवं राज्य से अलग करना शामिल था।[8] उसके सुधारों ने राज्य तंत्र के भीतर और बाहर कई सामाजिक स्तरों के हितों को बाधित किया, खासकर सामंती ज़मींदार। अपने विशेषाधिकार से वंचित, सामंती ज़मींदार और सर्वोच्च धार्मिक मंडल राज्य के खिलाफ जनमत को उकसाने में लगे हुए थे, इस बहाने कि राज्य ने इस्लामी कानूनों और परंपराओं का उल्लंघन किया। सामंती प्रभुओं और रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं के विरोध ने अंततः राजनीतिक संकट को जन्म दिया, जब 1929 में हबीबुल्लाह कलाकानी, एक ताजिक, जिसे बाचे-सकाव (जल वाहक का बेटा) के रूप में जाना जाता है, ने राजा अमानुल्लाह को उखाड़ फेंकने और देश में इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए सशस्त्र पुरुषों के एक समूह को इकट्ठा किया और काबुल पर हमला कर दिया। राजा अमानुल्लाह कंधार और फिर इटली भाग गए और वहां शरण ली।[9]

हबीबुल्लाह का अल्पवधि का शासन ध्वस्त हो गया क्योंकि वह सामाजिक विकास की ऐसी नीति की पेशकश नहीं कर सका जो आबादी को प्रभावित करे और न ही वह अपने शासन को मजबूत करने की स्थिति में था। इस वजह से उनके 9 महीने के शासन के अंत और जनरल मोहम्मद नादिर के उदय का रास्ता खुला। राज्य एवं उसके शासन को राज्य के प्रमुख के रूप में वैध बनाने हेतु राजा नादिर ने इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा दिया। उसने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए

आम तौर पर, अफ़ग़ान के इतिहास में, एक राजा और दूसरे के बीच सत्ता का परिवर्तन काफी उथल-पुथल वाला रहा है, ज़हीर शाह के उत्तराधिकार के एकमात्र अपवाद को छोड़कर, क्योंकि वास्तविक प्रशासनिक शक्तियाँ उनके चाचा, महामात्य मोहम्मद हाशिम (1930-1946) और शाह महमूद (1946-1953) के पास थीं।

इस्लाम का भी इस्तेमाल किया लेकिन हबीबुल्लाह को ऐसे ताजिक जातीयता के डाकू के रूप में दर्शाया जिसने पश्तूनों से सिंहासन छीन लिया हो।[10]

1930 में, राजा नादिर ने अफगानिस्तान के नए संविधान का समर्थन करने और उन्हें अफगानिस्तान का राजा बनाने हेतु लोया जिरगा (आदिवासी बुजुर्गों की महासभा) बुलाया। राजा के दायित्वों को तय करने के अलावा, इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि अफगानिस्तान के सभी भविष्य के राजा पश्तून जातीयता एवं इस्लाम के हनाफी स्कूल के होने चाहिए।[11] चूंकि राजा नादिर ने पश्तून जनजातियों की मदद से सत्ता पर कब्जा कर लिया, इसलिए उन्होंने उन्हें करों का भुगतान करने और सशस्त्र बलों में कार्य करने से छूट दी। उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने हेतु इन जनजातियों

पर भरोसा किया और "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई, एक जातीय समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उनकी अस्थिरता को बनाए रखा और फिर उन्हें अपने खिलाफ विद्रोह आयोजित करने से रोका।[12] 1933 में, राजा अमानुल्लाह के एक समर्थक द्वारा राजा नादिर की हत्या कर दी गई थी, और उनके 19 वर्षीय बेटे मोहम्मद ज़हीर ने उनकी गद्दी संभाली थी।

आम तौर पर, अफ़ग़ान के इतिहास में, एक राजा और दूसरे के बीच सत्ता का परिवर्तन काफी उथल-पुथल वाला रहा है, ज़हीर शाह के उत्तराधिकार के एकमात्र अपवाद को छोड़कर, क्योंकि वास्तविक प्रशासनिक शक्तियाँ उनके चाचा, महामात्य मोहम्मद हाशिम (1930-1946) और शाह महमूद (1946-1953) के पास थीं। उन्होंने धीमी गति वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर नादिर शाह का दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश की, जिससे समाज के पारंपरिक घटक प्रभावित न हो। उनके शासनकाल के दौरान, अमानुल्लाह के विरोध के कारण उलमाओं का प्रमुख धार्मिक वर्ग बहुत शक्तिशाली स्थिति में था; इस प्रकार, वैधता हेतु शासन को उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी थी। उन्होंने नागरिक और आपराधिक कानूनों पर धार्मिक तत्व को काफी हद तक महत्व देकर ऐसा किया। जहीर शाह के काल में, राज्य ने न केवल विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के उद्देश्य से बल्कि विरोध और आंतरिक प्रतिरोध को दबाने हेतु भी सेना और पुलिस बल का आधुनिकीकरण और सुसज्जित किया। राज्य के लिए राष्ट्रीय विचारधारा के निर्माण की नीति 1936 में तैयार की गई थी जब राज्य में पश्तो को देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने का प्रयास किया गया।

राज्य को "लोकतंत्र की ढाल" देने हेतु 1964 में एक नया संविधान पेश किया गया, जिसमें फारसी भाषा को पश्तो के समान दर्जा दिया तथा राजनीतिक दलों की स्थापना की अनुमति दी गई। संवैधानिक अवधि (1964-1973) के दौरान, चार प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्प्रभाव से नहीं निपट सका, जिस दौरान अफगानिस्तान में वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलना बंद हो गई दी। एक ओर देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से घिरा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर राज्य तंत्र के भीतर विभिन्न सामाजिक तबकों के संघर्षों से राज्य की वैधीकरण का संकट बढ़ा दिया। इस संकट से अंततः मोहम्मद दाउद द्वारा राज्य के

एक ओर देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से घिरा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर राज्य तंत्र के भीतर विभिन्न सामाजिक तबकों के संघर्षों से राज्य की वैधीकरण का संकट बढ़ा दिया।

अधिग्रहण और 1973 में अफगानिस्तान को गणतंत्र घोषित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1977 में, गणतंत्र हेतु एक नए संविधान को मंजूरी दी गई थी, जिसे दाउद खान ने संवैधानिक तरीके से राज्य बनाने के एक और प्रयास में समर्थन दिया था।

"शीत युद्ध" की स्पर्धा के दौरान इस देश को अपने पक्ष में करने की उम्मीद से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य (यूएसएसआर) से अफगानिस्तान को काफी अधिक

> कम्युनिस्ट काल (1978-1992) के दौरान, परंपरावादियों और आधुनिक विचारों से प्रभावित शहरी अभिजात वर्ग के बीच तनाव बढ़ रहा था।

विकास सहायता मिली। कम्युनिस्ट काल (1978-1992) के दौरान, परंपरावादियों और आधुनिक विचारों से प्रभावित शहरी अभिजात वर्ग के बीच तनाव बढ़ रहा था। शहरी अभिजात वर्ग की शिक्षा और समाज की अवधारणाओं तक पहुंच थी, जो स्थानीय गांव-आधारित पदानुक्रम और इस्लामिक पादरियों दोनों से आगे निकल गई, जिससे परंपरावादियों और आधुनिकतावादियों के बीच तनाव बढ़ गया।

सोवियत समर्थित सरकार ने सर्वसम्मति और सामाजिक सम्मेलनों पर अधिक ध्यान दिए बिना भूमि सुधार व्यवस्था सहित आठ फरमानों को जारी करके समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करना शुरू कर दिया।[13] 1979 में, अफगानिस्तान के भीतर एवं दोनों देशों में इस्लामी प्रतिरोध की बढ़ती आशंकाओं के जवाब में ईरान के नए घोषित इस्लामिक गणराज्य, यूएसएसआर ने वामपंथी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ अफ़ग़ानिस्तान (पीडीपीए) सरकार के समर्थन में देश में हस्तक्षेप किया, जो बाहरी शक्ति के अपने प्रॉक्सी के ज़रिए राज्य बनाने और नियंत्रित करने के प्रयास का स्पष्ट उदाहरण है। इस

अफगानिस्तान और मध्य एशिया आम तौर पर, लंबे समय तक शाही संरचना के अधीन, शीत युद्ध के दौरान विश्व राजनीतिक स्थिति में प्रमुखता से सामने आए क्योंकि यूएसएसआर पीडीपीए के मार्क्सवादी शासन और प्रमुख इस्लामी विद्रोही बल के बीच संघर्ष में उलझ गया था - मुजाहिदीन।

प्रकार, अफगानिस्तान और मध्य एशिया आम तौर पर, लंबे समय तक शाही संरचना के अधीन, शीत युद्ध के दौरान विश्व राजनीतिक स्थिति में प्रमुखता से सामने आए क्योंकि यूएसएसआर पीडीपीए के मार्क्सवादी शासन और प्रमुख इस्लामी विद्रोही बल के बीच संघर्ष में उलझ गया था - मुजाहिदीन।

1979 के अंत से लेकर फरवरी 1989 तक, सोवियत सैन्य बल अफगानिस्तान में रहा, ऐसी अवधि जब मुजाहिदीन का उग्र प्रतिरोध भी था, जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, विभिन्न खाड़ी देशों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी - आईएसआई, साथ ही साथ चीन और ईरान द्वारा भी द्वारा वित्तपोषित और सुसज्जित थे।[14] इस दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुजाहिदीन का समर्थन किया, जिन्हें वे इस्लामिक उग्रवादी होने के बावजूद "स्वतंत्रता सेनानी" मानते थे। ओसामा बिन लादेन उन लोगों में शामिल था जिन्हें अमेरिकी सहायता मिली थी, और उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन किया था।[15] दशक तक, सोवियत सेना अफगानिस्तान में उलझी रही, जबकि हजारों टन हथियार पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे गए। ये हथियार सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) और सऊदी अरब के पैसे से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, मिस्र और तुर्की के फंड से खरीदे गए थे।[16] मुजाहिदीन को बढ़ावा दिया गया, उनकी देखभाल की गई और उनकी हर जरूरत की आपूर्ति की गई और उन्हें हजारों शरणार्थियों में से भर्ती किया गया, जिन्होंने पड़ोसी पाकिस्तान में शरण ली थी। करीब 3 मिलियन अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में और 2 मिलियन ईरान में बस गए। इस अवधि के बाद से संघर्ष की वजह से विस्थापित अफगानों के कारण

दुनिया में सबसे बड़ा लंबा शरणार्थी संकट पैदा हुआ, और देश में बाद के शासन परिवर्तन (और राजनीतिक संकट) ने विदेशी देश में शरण लेने वाले अफगानों की संख्या में वृद्धि जारी रखी। विलियम मैले ने इंगित किया है कि अफगानिस्तान में युद्ध ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का ऐसा बहुस्तरीय विनाश उत्पन्न किया जो नई शताब्दी की शुरुआत में भी बड़े पैमाने पर मौजूद है।[17] अफगान राज्य के विघटन की प्रक्रिया 1980 के दशक में युद्ध के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन सोवियत की वापसी के बाद इसको बल मिला।

सोवियत संघ की वापसी के बाद भी, राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के अधीन मास्को समर्थित शासन 3 साल तक बना रहा। शासन ने कुछ नीतियों को बदल दिया जिससे उन्होंने सत्ता के अधिक पारंपरिक व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया और क्रांतिकारी बयानबाजी को भी छोड़ दिया।[18] 1992 और 1996 के बीच की अवधि में विभिन्न मुजाहिदीन गुटों ने सत्ता हथियाने हेतु एक-दूसरे से लड़ाई की,

अफगान के राजनीतिक परिदृश्य पर तालिबान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उभरा जब विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के बीच हिंसक गुटीय संघर्ष गृह युद्ध का रूप ले रहा था और शांति अपरिहार लग रही थी।

जिससे अफगानिस्तान में संघर्ष का एक नया चरण शुरू हुआ। सभी अलग-अलग गुट अपने क्षेत्रीय शक्ति प्रायोजकों, अर्थात् एक ओर पाकिस्तान और सऊदी अरब और दूसरी ओर ईरान, रूस, भारत व मध्य एशियाई राज्यों उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के हितों के लिए प्रॉक्सी का काम कर रहे थे। सोवियत युग के दौरान राज्य के अछूते संस्थान तेजी से विघटित हो गए, और जातीय विभाजन इतना अधिक था कि राजधानी काबुल को जातीय, भाषाई और धार्मिक रेखाओं के अनुसार बनाया गया था, जो बड़े पैमाने पर हजारा और गैर-हजारों (शिया व सुन्नी) के इस्लामी विश्वास के अनुयायियों के बीच बनायी गई थी। इस चरण में देखा गया कि कैसे जातीय कारकों और बाहरी देशों की भागीदारी ने अफगानिस्तान को एक विवादित क्षेत्र में बदल दिया, जिससे प्रत्येक बल अफगान राज्य बनाने हेतु दूसरे पर हावी होना चाहता था।

अफगान के राजनीतिक परिदृश्य पर तालिबान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उभरा जब विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के बीच हिंसक गुटीय संघर्ष गृह युद्ध का रूप ले रहा था और शांति अपरिहार लग रही थी। पश्तो भाषा में "तालिबान" शब्द का अर्थ "छात्र" है।[19] पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट (आईएसआई) के समर्थन से इस समूह का गठन 1990 के दशक की शुरुआत में डूरंड रेखा (अंग्रेजों द्वारा खींची गई अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान भूमि सीमा, जिसे अफगानिस्तान ने कभी भी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया) के पाकिस्तानी पक्ष के मदरसों और शरणार्थी शिविरों में किया गया था, जहां उन्हें आंतकवाद के लिए प्रेरित किया गया और उनका ब्रेनवाश किया गया। अपने देश को मौत तथा विनाश से मुक्त करने और शरीयत को लागू करने के दोहरे नारों के साथ अधिक से अधिक अफगान तालिबान आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ पर्यवेक्षकों ने इस आंदोलन

को एक ऐसा तंत्र बताया है जिसके द्वारा पाकिस्तान ने पश्तून पहचान (जो डूरंड रेखा के दोनों ओर रहने वाले पश्तून जातीयता के लोगों को जोड़ता है) को मिटाने "पश्तूनिस्तान" की मांग (ऐसी मांग जिसका पाकिस्तान को समय-समय पर सामना करना पड़ता था) को मोड़ने की कोशिश की। प्रारंभ में, तालिबान को एक स्थिर बल माना गया और संघर्षग्रस्त देश के निवासियों द्वारा जिसका स्वागत किया गया, जो इसे देश में शांति व सुरक्षा के लिए इस समूह की ओर देखते थे। तालिबान ने एक जातीय ताजिक राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी से राजधानी काबुल को छिन लिया, जिसे वे पश्तून विरोधी और भ्रष्ट माना जाता था। उस वर्ष, तालिबान ने अफगानिस्तान को एक "इस्लामिक अमीरात" घोषित किया, जिसमें मुल्ला मोहम्मद उमर, मौलवी और सोवियत विरोधी प्रतिरोध के अनुभवी, अमीर अल-मुमीनिन या "वफादारों के कमांडर" के रूप में नेता थे।

प्रारंभ में, तालिबान को एक स्थिर बल माना गया और संघर्षग्रस्त देश के निवासियों द्वारा जिसका स्वागत किया गया, जो इसे देश में शांति व सुरक्षा के लिए इस समूह की ओर देखते थे।

1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान, तालिबान ने शरिया या इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया और अफगान नागरिकों के खिलाफ नरसंहार, धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, भूख से मर रहे नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा खाद्य आपूर्ति करने से इनकार, सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट करने, महिलाओं को स्कूल जाने व अधिकांश रोजगार करने पर प्रतिबंध लगाने व अधिकांश संगीत पर प्रतिबंध लगाने हेतु निंदा की गई। महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार और बुनियादी अधिकारों से इनकार की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आलोचना की। महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंध और भेदभावपूर्ण नीतियों से उनका सार्वजनिक जीवन लगभग खत्म हो गया। सदाचार संवर्धन एवं दुर्गुण रोकथाम मंत्रालय ने महिलाओं को सिर से पांव तक बुर्का, या चादरी पहनना अनिवार्य कर दिया, संगीत व टेलीविजन पर प्रतिबंध लगा दिया और उन पुरुषों को जेल में डाल दिया जिनकी दाढ़ी बहुत छोटी थी।[20] हालांकि इस प्रारंभिक चरण के दौरान, वे केवल अतिरूढ़िवादी मिलिशिया थे, जिन्होंने बल द्वारा अपना शासन लागू किया, वे अभी तक एक आतंकवादी समूह नहीं थे। उनके शासन को केवल तीन देशों, अर्थात् पाकिस्तान, सऊदी अरब और

1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान, तालिबान ने शरिया या इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया और अफगान नागरिकों के खिलाफ नरसंहार, धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, भूख से मर रहे नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा खाद्य आपूर्ति करने से इनकार, सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट करने, महिलाओं को स्कूल जाने व अधिकांश रोजगार करने पर प्रतिबंध लगाने व अधिकांश संगीत पर प्रतिबंध लगाने हेतु निंदा की गई।

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मान्यता दी गई थी। तालिबान का अल कायदा द्वारा 9/11 के हमलों के जवाब में अमेरिकी आक्रमण के बाद 2001 में उखाड़ फेंकने से पहले देश के लगभग 90% हिस्से पर नियंत्रण था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लक्ष्य था: अल कायदा को कुचलना और तालिबान को जीतना। संयुक्त राष्ट्र ने "इस्लामिक अमीरात" पर विभिन्न प्रतिबंध लगाएं, जिन्हें 2001 में और कड़ा कर दिया गया।

बहुत ही कम समय में संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया था।

अल कायदा को सुरक्षित पनाहगाहों से बाहर निकालने हेतु अफगानिस्तान के अंदर जाने के उद्देश्य से शुरू मिशन अफगान को ऐसा सुरक्षित, स्थिर एवं लोकतांत्रिक राज्य बनाने के मिशन में बदल गया, जो समावेशी हो और अफगान लोगों के लिए लंबे समय तक ऐसा बना रहे। 2001 के बाद के रिपब्लिकन व्यवस्था जो अफगानिस्तान से तालिबान के हटने के बाद उभरी, उसे एक वैचारिक सुसंगतता प्राप्त थी। संकल्पनात्मक रूप से, इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान और 2003 में तैयार और पारित किया गया संविधान, उन चार प्रमुख ताकतों को एक साथ लाने में सक्षम रहा जिनका अफगान राजनीति में राज्य-गठन प्रक्रिया में प्रभाव था। इसमें अफगानिस्तान में विभिन्न बाहरी शक्ति के हितों को भी ध्यान रखा गया था - सभी महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पक्ष, क्षेत्रीय एवं वैश्विक दोनों, जिनका अफगान की राजनीति में दखल और भूमिका थी और किसी भी पक्ष को बाहर नहीं रखा गया था, हालांकि यह बिल्कुल तय था कि यहां अमेरिका का नेतृत्व था और अमेरिका देश में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। इसके ज़रिए विभिन्न शक्तियों की बुनियादी चिंताओं और संवेदनशीलताओं को दूर करने में कामयाबी मिली। कुल मिलाकर, 2001 के बाद के संविधान के सिद्धांत वैचारिक रूप से समृद्ध एवं सुसंगत थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगानिस्तान के राजनीतिक अभिजात वर्ग दोनों द्वारा कार्यान्वयन में कमी थी, जिन्हें अफगान गणराज्य के मूल्य और सिद्धांतों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगस्त 2021 में इसकी वजह से अफ़ग़ान गणराज्य का विघटन कैसे हुआ, यह समझने हेतु निम्न खंड में मोटे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति प्रक्षेपवक्र और राजनीतिक अभिजात वर्ग की भूमिका पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है।

कुल मिलाकर, 2001 के बाद के संविधान के सिद्धांत वैचारिक रूप से समृद्ध एवं सुसंगत थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगानिस्तान के राजनीतिक अभिजात वर्ग दोनों द्वारा कार्यान्वयन में कमी थी, जिन्हें अफगान गणराज्य के मूल्य और सिद्धांतों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

2. अमेरिका का हटना एवं अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य का विघटन

अफगानिस्तान "संकट" और तालिबान की शासन-प्रणाली

अफगान राज्य के पतन के कारणों को चिन्हित करने हेतु पिछले 20 वर्षों के इतिहास को खंगालना इस शोधपत्र के दायरे में नहीं आता है। तालिबान की जीत और अफगान सरकार तथा उसकी सेना के अचानक पतन का कोई एक कारण नहीं था। फिर भी वर्तमान अफगानिस्तान को समझने हेतु इस खंड में उन प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है जिसके कारण अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाया गया, और इसमें यह तर्क देकर निष्कर्ष निकाला गया कि वापसी की घोषणा एक महत्वपूर्ण कारक थी जिसने तालिबान को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद इसमें संक्षेपतः और व्यापकतः उन कई कारकों पर चर्चा की गई है जो अफगान गणराज्य के विघटन के कारण बने।

<u>15 अगस्त 2021 तक प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम</u>

2003 या 2004 तक, अमेरिका को लगा कि उसने अफगानिस्तान में अल कायदा को खत्म करने का अपना मिशन पूरा कर लिया है, भले ही बिन लादेन अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। इसके

2003 या 2004 तक, अमेरिका को लगा कि उसने अफगानिस्तान में अल कायदा को खत्म करने का अपना मिशन पूरा कर लिया है, भले ही बिन लादेन अभी भी उनकी पहुंच से दूर था।

पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान इराक में सद्दाम हुसैन की ओर गया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान अफगानिस्तान से हट गया। इस दौरान तालिबान को खुद को पुनः संगठित होने का मौका मिला, और वे पाकिस्तान स्थित अपने सुरक्षित पनाहखानों से वापस अफगानिस्तान की ओर आने लगे। अफगानिस्तान में, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी क्रूर मारक क्षमता से तालिबान को निशाना बना रहा था, लेकिन इसमें नागरिकों की भी जान जा रही थी। यह वह समय भी था जब अफगान नागरिक अमेरिकी सेना की रूढ़िवादी समाज की भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाइयों से असंतुष्ट हो रहे थे। नतीजतन, "विदेशी कब्जे" की बात उभरने लगी, जिसका फायदा तालिबान को हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में हस्तक्षेप के दस साल पश्चात, वाशिंगटन में राजनीतिक समाधान का दबाव बढ़ रहा था। फरवरी 2011 में, अमेरिकी विदेश मंत्री, हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी नीति में बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत हेतु पूर्व शर्तों - "विद्रोहियों को हथियार डालने और हिंसा छोड़ने, अफगान संविधान के ढांचे को स्वीकार करने एवं अल कायदा से अलग होने" को मान्यता दी।[21] यह राष्ट्रपति बराक ओबामा के अनुसार ऐसी "बड़ी घटना" थी, जिससे जमीन पर सैन्य स्थिति में बदलाव होना था। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 17 जून 2011 को संकल्प 1988 को अपनाया, जिससे 1999 में संकल्प 1267 के तहत स्थापित अल कायदा प्रतिबंध सूची से तालिबान प्रतिबंध सूची को अलग कर दिया। इसके बाद 17 दिसंबर 2012 को सुरक्षा परिषद संकल्प 2082 आया, जिसने तालिबान से जुड़े सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंधों को हल्का कर दिया ताकि वे यात्रा कर सके एवं शांति व सुलह वार्ता में भाग ले सकें। इससे "शांति और सुलह" का मार्ग प्रशस्त हुआ, और ऐसे में तालिबान समझ गया था

कि अमेरिकी युद्ध से थक चुके थे और इसलिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार, कई घटनाओं की वजह से ओबामा प्रशासन के समर्थन से दोहा में तालिबान का कार्यालय खोलने का रास्ता खुला, जो किसी आतंकवादी समूह के वैधीकरण की दिशा में एक शुरुआती कदम था।

इस अवधि के दौरान, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को संचार एवं आपूर्ति की जमीनी लाइन प्रदान करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान पर सबसे अधिक निर्भर था। दूसरी ओर, पाकिस्तानियों ने दोतरफा खेल खेला - उन्होंने अमेरिकियों की मदद की, साथ ही तालिबान आंदोलन की मदद की, जो तब तक विद्रोह में बदल गया था। ये सभी घटनाक्रम अमेरिकी एडमिरल माइक मुलेन द्वारा सार्वजनिक तौरपर हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की आईएसआई की "वास्तविक शाखा" कहने के साथ-साथ हो रहे थे।[22] पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए राज्य सचिव हिलेरी क्लिंटन ने हक्कानी नेटवर्क पर "दबाव" बनाने हेतु अधिक सहयोग की मांग करते हुए कहा कि: "आप सांप पालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं की वह केवल आपके पड़ोसियों को ही काटेगा"।[23] हालांकि राष्ट्रपति बुश द्वारा पाकिस्तान को समस्या का केंद्र बताए जाने के पश्चात से वाशिंगटन में लगातार व्यवस्थाएं कीं, लेकिन वे इस मुद्दे को हल करने हेतु कभी ठोस कदम नहीं उठा सके। इसके विपरीत, वे पाकिस्तान को उसकी हरकतों की परवाह किए बिना इनाम देते रहे। 2018 में, तालिबान के सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कथित तौर पर अमेरिकी प्रशासन से बातचीत करने हेतु वाशिंगटन के इशारे पर एक पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया था, जो तालिबान और आईएसआई की सफलता का संकेत था।

विभिन्न चर्चाएं शुरू हुईं। पाकिस्तान यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तालिबान को कई देश स्वीकार करें, और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान और तालिबान के साथ चतुर्भुज समन्वय परिषद की शुरुआत हुई। इस्तांबुल द्वारा "हार्ट ऑफ़ एशिया" प्रक्रिया की मेजबानी की गई थी। रूस भी ट्रोइका - संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन की तिकड़ी के रुप में इसमें शामिल हो गया, जिसने पाकिस्तान को शामिल किया और फिर मास्को मंच को जोड़ा जिसमें अफगानिस्तान,

> संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच कई वार्ता के पश्चात फरवरी 2020 में दोहा, कतर में उस समय की अफगान सरकार की अनुपस्थिति में अमेरिका-तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहरहाल, इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ।

तालिबान व क्षेत्रीय देश शामिल थे। इस बीच, दोहा में तालिबान समूह मीडिया एवं कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी को संभालने में निपुण हो रहा था, जबकि यूएसए ने 31 दिसंबर 2014 को ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का समापन करके अपने युद्ध अभियानों को समाप्त कर दिया और ऑपरेशन रेसोल्यूट सपोर्ट शुरू किया,[24] जिससे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) की भूमिका अफगान बलों को "प्रशिक्षण, सलाह एवं सहायता" करने तक सीमित हो गई, क्योंकि अफगान बल अब युद्ध में नेतृत्व करना शुरू कर चुके थे। ओबामा के कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी सैनिकों

की संख्या घटकर 8600,[25] हो गई और ट्रम्प प्रशासन ने इस संख्या को और घटाकर 2500 कर दिया।

2018 में एक बड़ी सफलता मिली जब ट्रम्प प्रशासन ने अफगानिस्तान सुलह हेतु राजदूत ज़ल्माय ख़लीलज़ाद को विशेष दूत नियुक्त किया, जिन्होंने तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू की। यह वैधता प्रक्रिया का अलग चरण था। खलीलज़ाद ने यह रेखांकित करते हुए कि "कुछ बात पर सहमति नहीं बल्कि हर बात पर सहमति होनी चाहिए", चार उद्देश्य - युद्धविराम, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट व अन्य आतंकवादी समूहों के साथ संबंधों को काटना, अंतर-अफगान शांति वार्ता और विदेशी ताकतों की वापसी के साथ अपना काम शुरु किया।[26] अन्य मुद्दों में बहुत कम प्राथमिकता दी गई और बिना किसी समय सीमा के दरकिनार कर दिए गए।

संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच कई वार्ता के पश्चात फरवरी 2020 में दोहा, कतर में उस समय की अफगान सरकार की अनुपस्थिति में अमेरिका-तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहरहाल, इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हुआ। "उस अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के साथ अफगानिस्तान में शांति हेतु समझौता, जिसे अमेरिका द्वारा राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है और जिसे तालिबान एवं यूएसए के रूप में जाना जाता है"[27] पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उस समय किसी ने भी इन दो संस्थाओं के बीच हुए एक अनोखे समझौते पर सवाल नहीं उठाया जिन्होंने एक दूसरे को मान्यता नहीं दी थी। इसके अलावा, इस समझौते को "शांति समझौते" के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था, जो अनुचित था, क्योंकि यह मूलतः सैनिकों को वापस बुलाने का समझौता था।

1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी इस समझौते का महत्वपूर्ण प्रावधान थी, जिसपर बिना किसी कठिनाई के सभी ने सहमति व्यक्त की। समझौते में शायद ही कोई शर्त, चाहे वह व्यापक युद्धविराम हो या अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रक्रिया, तालिबान पर थोपी गई थी। अंतर-अफगान वार्ता पर एक समझौता हुआ, जो अंततः 12 सितंबर 2020 को दोहा में कई प्रमुख हितधारकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपस्थिति में बहुत धुमधाम से शुरू हुआ, लेकिन अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान पर जो अंतिम उपकार किया था, वह अफगान सरकार को शांति वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु 5000 से अधिक तालिबान कैदियों को रिहा करने के लिए "मनाना" था, जिससे इसके आगे हाशिए पर जाने की संभावना बढ़ गई थी। उन मुक्त कैदियों में से कुछ बाद में युद्ध और 2021 में देश भर के शहरों के खिलाफ तालिबान के हमले में शामिल हो गए।[28]

पदभार ग्रहण करने के बाद से ही राष्ट्रपति बिडेन के सामने या तो 1 मई की समय सीमा को बनाए रखने या अन्य रास्ते तलाशने का विकल्प था। अफगानिस्तान में एक पूर्व भारतीय दूत, राजदूत राकेश सूद ने तर्क दिया है कि, "उनके पास हमेशा के लिए युद्धों से संबंधित गलत बातों को बदलने या सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने यह घोषणा करते हुए कि ओसामा बिन लादेन को मारकर तथा अल कायदा को नष्ट करके अमेरिका का मिशनल पूरा हो

गया है, अपने उद्देश्य को पुनः तय करते हुए अपनी रक्षक की भूमिका को त्यागने का विकल्प चुना, और अमेरिकी लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा ड्रोन जैसे आसमान में मौजूद विकल्पों द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।[29] अपनी 14 अप्रैल 2021 की घोषणा में, राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि "अफगानिस्तान में युद्ध पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला युद्ध नहीं था" और अमेरिका ने वह लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जिनके लिए वह अफगानिस्तान गया था और "यह (अमेरिका के लिए) हमेशा के लिए युद्ध को समाप्त करने का सही समय है।"[30] अफगानिस्तान पर प्रसिद्ध टिप्पणीकार, रोरी स्टीवर्ट तर्क दिया, "अफगानिस्तान में विगत बीस वर्षों में जो प्रगति हुई है, उसे 2500 सैनिकों (अंत में) की एक बहुत ही कम अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, पिछले पांच वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बलों की बहुत कम हताहतों की संख्या को देखते हुए लगभग अनिश्चित समय तक बनाए रखा जा सकता था।[31] बिडेन की घोषणा के बाद, नाटो सहयोगियों ने भी अपने शेष 8000 सैनिकों को वापस हटाने का फैसला किया।[32] इस फैसले ने काबुल को पुनः हासिल करने की तालिबान की दशकों पुरानी महत्वाकांक्षा को गति दी।

जून-जुलाई 2021 तक, तालिबान अपने गैर-पारंपरिक क्षेत्रों जैसे उत्तर व उत्तर पूर्व, साथ ही साथ अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्सों में घुस गया। दूसरे चरण में, उन्होंने सीमा पार के हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जो काफी महत्वपूर्ण थे। तालिबान ने कथित तौर पर अफगान सेना के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मनाने हेतु अपनी "मजबुत स्थिति" का इस्तेमाल किया और अपने सोशल

भले ही दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों का मानना था कि तालिबान के लिए प्रांतीय केंद्रों पर कब्जा करना या पकड़ बनाना एवं प्रमुख शहरों को छोड़ देना आसान नहीं होगा, अंत में कुछ दिनों के अंतराल में सभी प्रांतीय केंद्र और प्रमुख शहर पर उनका कब्जा हो गया।

मीडिया चैनलों और हैंडल पर आत्मसमर्पण के वीडियो अपलोड किए। अंत में, भले ही दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों का मानना था कि तालिबान के लिए प्रांतीय केंद्रों पर कब्जा करना या पकड़ बनाना एवं प्रमुख शहरों को छोड़ देना आसान नहीं होगा, अंत में कुछ दिनों के अंतराल में सभी प्रांतीय केंद्र और प्रमुख शहर पर उनका कब्जा हो गया। वापसी की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1 जुलाई 2021 को यूएसए द्वारा बगराम एयरबेस को छोड़ने का तरीका था। लगभग 20 वर्षों के बाद, अमेरिका बेस के नए अफगान कमांडर को सूचित किए बिना मध्य रात में बिजली बंद करके देश के अपने सबसे बड़े हवाई क्षेत्र से चुपके से बाहर निकल गया, जिन्हें अमेरिकियों के जाने के 2 घंटे से अधिक समय बाद इसका पता चला।[33] वहां से न केवल 2500 अमेरिकी बल वापस बुलाए गए, बल्कि उन्होंने अपने साथ अफगान समकक्ष को सूचित किए बिना 17,000 ठेकेदार भी ले गए, जो अफगान वायु सेना को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे।[34] इस घटना पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब[35] ने बाद में कहा: "हमारी वायु सेना के लिए किसी प्रकार का गोला-बारूद नहीं था। कोई हवाई निर्देशित मिसाइल नहीं थी, कोई नजदीकी हवाई सहायता उपलब्ध नहीं थी, फिक्स्ड विंग विमान में लड़ने हेतु आवश्यक गोला-बारूद नहीं था"; उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी ठेकेदार ऐसा तार्किक दृष्टिकोण से कर रहे थे, इसलिए उनके अचानक जाने ने अफगान वायु सेना की लड़ने की क्षमता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अन्य बातों के अलावा, इस फैसले का जमीन पर लड़ रहे अफगान सैनिकों के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ा।

अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित एवं सुसज्जित अफगान सेना कुछ ही महीनों के भीतर हार गई, इससे उसने कई पर्यवेक्षकों को झकझोर कर रख दिया था। नांगरहार प्रांत के पूर्व गवर्नर जियाउलहक अमरखिल ने पश्तो में टोलो न्यूज से बात करते हुए कहा कि तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत ने न केवल अफगानिस्तान में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर किया बल्कि काबुल में नागरिक व्यवस्था के पतन की नींव भी रखी।[36] अफगान सेना को अमेरिकी सेना ने तैयार किया था,

---

2001 के बाद अफ़गानिस्तान को मिलने वाला अधिकांश धन भ्रष्ट ढांचे को बनाने में बर्बाद हो गया, जबकि तालिबान अपने स्थानीय स्रोतों एवं जबरन वसूली से कहीं अधिक सस्ते में अपने कार्यों को वित्तपोषित कर सकता था, और अपना लगभग सारा पैसा भ्रष्टाचार के बजाय अपने लक्ष्यों व संचालन पर खर्च कर सकता था।

और इसकी नींव परिष्कृत टोही इकाइयों, ड्रोन व हवाई निगरानी और हवाई समर्थन का उपयोग करके वास्तविक समय की खुफिया जानकारी पर आधारित थी। 2014 के बाद से, अफ़गानों ने युद्ध में नेतृत्व किया और इस प्रक्रिया में 50,000 से अधिक सुरक्षा बलों को खो दिया, जबकि सैनिक कार्रवाई में मारे जाने वाले अमेरिकी एवं नाटो सैनिकों की संख्या सौ से भी कम थी, जिससे उनकी लड़ाई की क्षमता प्रदर्शित होती है। निस्संदेह, व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था और इसने मनोबल को प्रभावित किया, लेकिन संस्था निर्माण का उद्देश्य कभी भी त्वरित कार्य नहीं होना चाहिए था। एंथोनी एच. कोर्ड्समैन की एक रिपोर्ट[37] में इसके कारकों की पहचान करने का प्रयास किया गया, और निम्नलिखित मुद्दों में से कुछ की ओर इशारा किया गया। सबसे पहला, दाता राज्यों एवं अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) के नागरिक और सैन्य सहायता प्रयासों का ठीक से समन्वय नहीं किया गया था, और एकीकृत नागरिक सैन्य संरचना बनाने के प्रयास प्रभावी नहीं थे। दूसरा, अफगानिस्तान अपनी आय के लगभग 80% के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर बना रहा, और नार्को-तस्करी (जो सरकार की आय नहीं थी) अफगानिस्तान के निर्यात का प्रमुख स्रोत था। 2001 के बाद अफ़गानिस्तान को मिलने वाला अधिकांश धन भ्रष्ट ढांचे को बनाने में बर्बाद हो गया, जबकि तालिबान स्थानीय स्रोतों एवं जबरन वसूली से कहीं अधिक सस्ते में अपने कार्यों को वित्तपोषित कर सकता था, और अपना लगभग सारा पैसा भ्रष्टाचार के बजाय अपने लक्ष्यों व संचालन पर खर्च कर सकता था। तीसरा, 2007 के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो तथा अफगान सरकार ने अफगान बलों के संगठन, प्रशिक्षण, उपकरण और नेतृत्व में समस्या होने की बात से इनकार किया, और उन्होंने दोनों बलों के विकास और खुले युद्ध में सफल होने की बात कही। चौथा, अफगान सेना का वास्तविक लड़ाकू कोर बहुत छोटा था, युद्ध के बोझ से दब गया, और वे अपने संचालन हेतु सक्रिय अमेरिकी खुफिया, लड़ाकू सेना के समर्थन, वायु शक्ति और ठेकेदारों पर अत्यधिक निर्भर थे। अंतरराष्ट्रीय सैनिकों के हटने से मदद खत्म हो गई। आपूर्ति श्रृंखलाओं के ढह जाने के कारण आगे के ठिकानों पर गोला-बारूद की पुनःपूर्ति रुक गई। चिकित्सा निकासी अब संभव नहीं थी - विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जमीन पर खड़े रखने पड़े। जीपीएस

ट्रैकिंग और लक्ष्यीकरण व्यवस्था समाप्त हो गई क्योंकि हथियार प्रणालियों से मुख्य सॉफ्टवेयर हटा

> महासंघ के समेकन में यूएई की राजनीतिक कठिनाइयों ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी प्रारंभिक बातचीत पर एक अमिट छाप छोड़ी जो बाद में जीसीसी के सदस्य बने।

> अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करते हुए शीर्ष अफगान नेतृत्व और देश के भ्रष्ट राजनीतिक अभिजात वर्ग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।

दिया गया था। सैनिकों को सेना की तरह लड़ने हेतु प्रशिक्षित किया गया था, गुरिल्ला के रूप में नहीं; इस प्रकार, वे पंगु हो गए।[38] जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका बगराम से हटा, उसने अफगानिस्तान के हाल के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अफगान गणराज्य का विघटन हुआ और 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया।

अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करते हुए शीर्ष अफगान नेतृत्व और देश के भ्रष्ट राजनीतिक अभिजात वर्ग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। शायद इसकी सबसे संक्षिप्त व्याख्या न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑप-एड में अफगान सेना के तीन-सितारा जनरल सैमी सबेट ने की थी, "हमें राजनीति एवं राष्ट्रपतियों द्वारा धोखा दिया गया था।"[39] युद्ध के पूरे इतिहास में, अफगान सरकार की विफलताओं की वजह अप्रभावी और निराशाजनक अस्थिर नेतृत्व द्वारा संचालन था। उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय हित के विपरीत स्व-हित से प्रेरित राजनीति एक बड़ी चुनौती थी। शक्तिशाली पदों पर आसीन कई अफगान कुलीनों के पास दोहरी नागरिकता थी, जो 2001 के बाद पश्चिमी देशों से अफगानिस्तान लौटे थे, जहां उन्होंने पहले की अवधि के दौरान निर्वासन की मांग की थी और उन देशों के नागरिक थे। इसलिए, जब उन्होंने महसूस किया कि अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ रही है, तो वे बिना किसी समस्या के निकल सकते थे - देश और इसके लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही सबसे कम थी।

तालिबान शासन की जगह लेने वाली "अफगान की अंतरिम सरकार" को लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तालिबान की बमबारी से पैदा हुए हमले में पुराने कमांडर और गुट आ गए थे जो पहले अमीरात के दौरान तालिबान से हार गए थे - या प्रतिरोध में लटके हुए थे। तालिबान को खदेड़ने में अमरीकियों की मदद करके, उन्होंने प्रांतीय और जिला, मंत्रालयों, सेना कोर एवं पुलिस मुख्यालय दोनों में शासन पर कब्जा कर लिया। पहले कैबिनेट के लगभग चार-पांचवें सैन्य पुरुष या तंजीम (राजनीतिक-सैन्य गुट) के नागरिक सदस्य थे। पहले 30 प्रांतीय गवर्नरों में से

कम से कम 20, एंटोनियो गिउस्टोज़ी ने आकलन किया, "मिलिशिया कमांडर, सरदारों या मजबूत व्यक्ति" थे, जबकि "छोटे मिलिशिया कमांडरों को भी जिला गवर्नरों के रैंकों पर रखा गया"।[40] 2001 के बाद के राज्य में सत्ता की स्थिति हासिल करने वालों ने तब बाहर से आए पुरुष, संरक्षण नेटवर्क और संगठनात्मक संरचनाएं जो कई वर्षों के युद्ध के बाद तालिबान राज्य में विकसित हुईं, फिर से राजनीतिक क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया।[41] सत्ता की यह हड़प, जिसे अमेरिकी समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग द्वारा बनाए रखा गया था, पूरे अफगानिस्तान में देखा गई और अगले 20 वर्षों के लिए गणतंत्र की प्रकृति को आकार दिया।

इन सबके बावजूद, लोगों के बीच अफगान गणराज्य के प्रति स्वामित्व की भावना, आशा और संभावना की भावना थी, हालांकि वे इस अवधि के दौरान राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक अभिजात वर्ग के अत्यधिक आलोचक बने रहे।

स्थानीय प्रभाव के अलावा, सेनापतियों को राजनीतिक वैधता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय देशों से नकद सहायता सहित वित्तीय सहायता से लाभ हुआ।[42] सेनापतियों के बढ़ते प्रभाव और जातीय-आधारित सत्ता-साझाकरण राजनीतिक प्रणाली की मांग ने तालिबान के बाद के राज्य-निर्माण के प्रयासों के पहले चरणों में केंद्रीय राज्य मॉडल के पुनर्निर्माण के सामने गंभीर चुनौती पेश की।[43] युद्ध के पहले के विपरीत, जब राज्य में सामाजिक नियंत्रण की शीर्ष-नीचे रणनीति तैयार की, तो नए सत्ताधारियों ने राज्य के साथ अपने संबंधों पर फैसला किया। जब आकर्षक सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया, तो संबंध सहयोगी थे, लेकिन यदि पद से बर्खास्त कर दिया गया, तो मैत्रीपूर्ण संबंध शत्रुता में बदल जाते थे। इसके अलावा, सत्ता, स्थिति तथा मौद्रिक लाभ हेतु देश के शीर्ष नेताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा, कभी-कभी राष्ट्रीय हित को नज़रअंदाज करने का (जो पिछले 20 वर्षों में प्रत्येक राष्ट्रपति चुनाव से पहले और बाद में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी) का गंभीर प्रभाव पड़ा। केंद्रवादी राज्य और उसके नेताओं का स्थानीय समुदायों के साथ, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक संबंध का अभाव था, और समय बीतने के साथ यह अंतर केवल बढ़ता ही गया। बीबीसी के पत्रकार डेविड ल्योन (जिन्होंने राष्ट्रपति गनी 2017-2018 के संचार सलाहकार के रूप में कार्य किया) ने अपनी हालिया पुस्तक द लॉन्ग वॉर में कहा, “पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अलग-थलग रहते थे, उनका विशाल मैनीक्योर लॉन से परे देश से बहुत कम संपर्क था...उन्होंने बहुत कम लोगों पर भरोसा किया, और कुछ लोगों के बारे में उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने हित में उनकी पहुंच का फायदा उठाया।'[44] सरकारी प्रयासों का बहुत अधिक हिस्सा ऐसे देश के संसाधनों पर संघर्ष की बलि चढ़ गया था जहां कर्मियों पर नियंत्रण संरक्षण नेटवर्क के माध्यम से सत्ता हासिल करने में मदद करता है।[45] इन सबके बावजूद, लोगों के बीच अफगान गणराज्य के प्रति स्वामित्व की भावना, आशा और संभावना की भावना थी,

हालांकि वे इस अवधि के दौरान राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक अभिजात वर्ग के अत्यधिक आलोचक बने रहे। आखिरकार, जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके सहयोगी 15 अगस्त को सबसे महत्वपूर्ण वक्त में काबुल से भाग गए, उन्होंने केवल यही उदाहरण दोहराया कि नेतृत्व के प्रति उनका अविश्वास और गुस्सा गलत नहीं था।

3. अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी

मई से अगस्त 2021 तक, बढ़ती असुरक्षा, लक्षित हत्याओं और नागरिकों पर हो रहे लक्षित हमलों के बीच, तालिबान ने सैन्य हमले के ज़रिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, जो धीर-धीरे देश

मई से अगस्त 2021 तक, बढ़ती असुरक्षा, लक्षित हत्याओं और नागरिकों पर हो रहे लक्षित हमलों के बीच, तालिबान ने सैन्य हमले के ज़रिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, जो धीर-धीरे देश भर में फैल गया, 15 अगस्त को राजधानी शहर तक पहुंच गया।

भर में फैल गया, 15 अगस्त को राजधानी शहर (चित्र 1 देखें) तक पहुंच गया। इस खूनी दिन की शाम तक, पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने सहयोगियों के साथ देश से भाग गए और "विजय" प्राप्त

तालिबान शासन से बचने के लिए अमेरिकी वायु सेना के विमान से अफ़ग़ानों के चिपके रहने की फुटेज पश्चिमी शक्तियों द्वारा दशकों से चली आ रही सैन्य हस्तक्षेप की एक छवि बनी रहेगी।

कर चुके तालिबान ने एआरजी, राष्ट्रपति महल,[46] और काबुल में कई सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया और "युद्ध समाप्ति" की घोषणा कर की।[47] उन्होंने घोषणा की, "हम वहां तक पहुँच गए हैं जिसकी हम तलाश थी, हमारे देश की आज़ादी और हमारे लोगों की आज़ादी।"[48] अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बलों ने 15 अगस्त से काबुल के हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया, जब तक कि 31 अगस्त को अमेरिकी कर्मी वहां से नहीं निकल गए। काबुल हवाईअड्डे पर अराजकता की स्थिति थी, हजारों लोग अफगानिस्तान से भागने के लिए फ्लाइट तक पहुंचने की उम्मीद में इसके आसपास इकट्ठा हुए। तालिबान शासन से बचने के लिए अमेरिकी वायु सेना के विमान से अफ़ग़ानों के चिपके रहने की फुटेज पश्चिमी शक्तियों द्वारा दशकों से चली आ रही सैन्य हस्तक्षेप की एक छवि बनी रहेगी। 26 अगस्त को, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसआईएल-केपी) ने हवाई अड्डे के बाहर एक आत्मघाती हमला किया जिसमें 72 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इस अराजकता के बीच, "समावेशी" सरकार को लेकर कुछ बातें उठीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि तालिबान ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि वह पहले ही "विजय" प्राप्त कर चुका था। तालिबान नेतृत्व में जमीन पर लड़ने वाले लोग दोहा में अमेरिकियों के साथ बातचीत कर रहे लोगों से अलग थे। राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिन्हें मुल्ला उमर के जीवनकाल में भी डिप्टी घोषित किया गया था, की तालिबान की इस संरचना में प्रमुख उपस्थिति नहीं थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्चर्य हुआ। जो गुट सबसे अधिक सक्रिय था, वह सशस्त्र गुट था- हक्कानी समूह उनमें सबसे प्रमुख था। अगले कुछ महीनों के भीतर, कई समस्याएं सामने आ गईं।

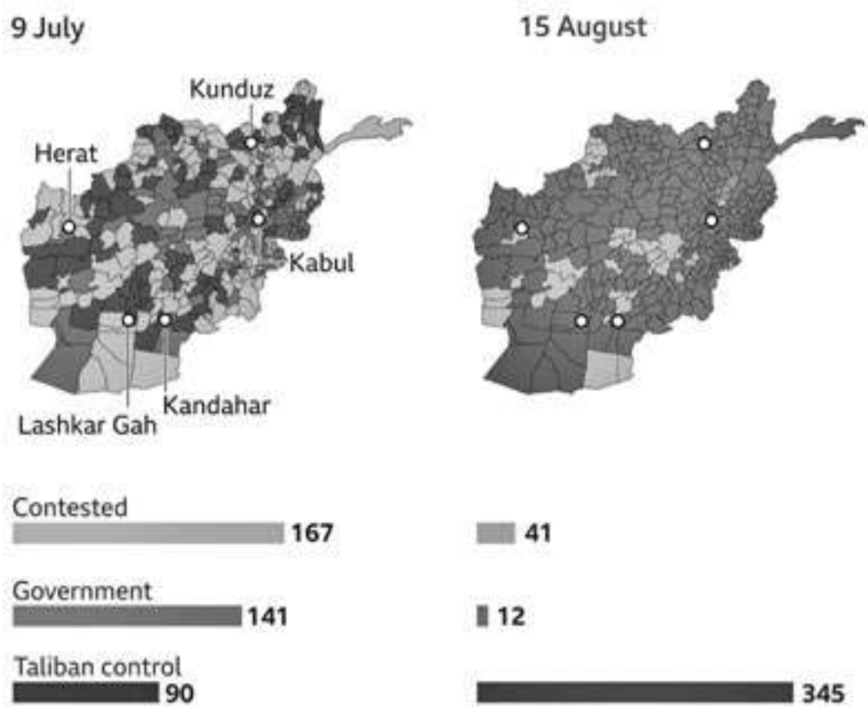

चित्र 1. 9 जुलाई से 15 अगस्त 2021 के बीच तालिबान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र

पहली समस्या तालिबान और देश के बाकी हिस्सों के बीच थी, जिनमें से अधिकांश तालिबान के पक्षधर नहीं थे। प्रतिरोध ने विभिन्न रूप धारण किए, चाहे वह अफगान बहुलवाद के प्रतीक के रूप में झंडे द्वारा विरोध हो (जिसमें अफगानों ने अफगान ध्वज को हटाने पर आपत्ति जताई थी)[49], कामकाजी अधिकार चाहने वाली महिलाओं द्वारा विरोध या लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में विरोध हो। दूसरी समस्या तालिबान और तालिबान विरोधी समूहों जैसे राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा (एनआरएफ) के

जहां तक अपनी विदेश नीति का संबंध है, क्षेत्र के भीतर और बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए, यूएई साहसिक कदम उठाने से नहीं कतरा रहा है।

बीच संघर्ष में देखी जाती है, जो एक सैन्य गठबंधन है और प्रसिद्ध ताजिक कमांडर अहमद शाह मसूद के पुत्र अहमद मसूद के नेतृत्व में कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और अफगानिस्तान इस्लामिक नेशनल एंड लिबरेशन मूवमेंट जैसे नए समूहों ने भी पिछले कुछ महीनों में छोटे इलाकों में प्रतिरोध करने का दावा किया है।[50] तीसरी समस्या इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) और तालिबान के बीच संघर्ष है। तालिबान के कब्जे के बाद, आईएसकेपी ने अपने हमलों को जारी रखा, इस बार तालिबान को विद्रोही प्रतिद्वंद्वियों के रूप में नहीं बल्कि अवैध शासक अधिकारियों के रूप में लक्षित किया। अंत में, तालिबान आंदोलन के भीतर गुटबाजी - कथित तौर पर आंदोलन का नेतृत्व - वर्तमान में कम से कम तीन समूहों में विभाजित है। पहला समूह दोहा समूह है जिसमें मुल्ला बरादर के नेतृत्व में अमेरिकी शांति वार्ता दल शामिल है, दूसरा मुल्ला उमर के बेटे मोलवी याकूब के नेतृत्व वाली सैन्य शाखा है, और तीसरा सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व वाला हक्कानी नेटवर्क विंग है।[51] सबसे महत्वपूर्ण और संभावित रूप से प्रभावित विवाद हक्कानी और याकूब के बीच असहमति है, जिसके बारे में कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई है।[52] हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न गुटों के बीच दरार के बारे में लगातार अफवाहों के बावजूद, तालिबान अभी तक एक समेकित मोर्चा बनाने में कामयाब रहे हैं।

तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान

7 सितंबर 2021 को, तालिबान ने 33-सदस्यीय, पूरी तरह से पुरुष सदस्यों वाले "कार्यवाहक कैबिनेट" की घोषणा की, जिसमें ज्यादातर पश्तून तालिबान एवं हक्कानी दिग्गज, कट्टरपंथी और वफादार व्यक्ति शामिल थे, जिसमें केवल 2 ताजिक व 1 उज़्बेक, और कोई हज़ारा नहीं था, जिसका नाम सेटअप में रखा गया था।[53] नवंबर 2022 में, उन्होंने तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदज़ादा,[54] के आदेशों का अनुपालन करते हुए 27 नए सदस्यों को शामिल करके अपने अंतरिम

> अफगानिस्तान का राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य विगत वर्षों की तुलना में बहुत अलग है। अफगान परिदृश्य में प्रमुख किरदार तथाकथित इस्लामिक अमीरात (जिसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है) हैं, जिसमें दो प्रमुख घटकों के रूप में हक्कानी नेटवर्क और अन्य तालिबान गुट हैं।

मंत्रिमंडल का विस्तार किया, हालांकि, इससे भी कैबिनेट का जातीय या लिंग संतुलन नहीं बदल सका। अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने के बाद, तालिबान ने पूरे देश को "माफ" करने की घोषणा की थी। एक संवाददाता सम्मेलन में, तालिबान के प्रवक्ता, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आश्वासन दिया कि तालिबान बदला नहीं लेना चाहता है और "सभी को माफ़ कर दिया गया है।"[55] हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, ऐसी कई रिपोर्टें आईं जिससे इसके विपरीत होने की जानकारी मिलती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के पहले 4 महीनों में अफगानिस्तान में 100 से अधिक न्यायेतर हत्याओं के "विश्वसनीय आरोप" थे, जिनमें से अधिकांश दोष देश के नए शासकों पर थे। कई मामलों में, निकायों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था जैसा कि सत्ता में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान किया गया था। 15 अगस्त 2021 और 15 जून 2022 के बीच, यूएनएएमए ने 160 न्यायेतर हत्याएं, 178 मनमानी गिरफ्तारियां और हिरासतें, 23 अनौपचारिक हिरासत और पूर्व अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों की यातना और दुर्व्यवहार की 56 घटनाएं दर्ज कीं।[56]

अफगानिस्तान का राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य विगत वर्षों की तुलना में बहुत अलग है। अफगान परिदृश्य में प्रमुख किरदार तथाकथित इस्लामिक अमीरात (जिसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है) हैं, जिसमें दो प्रमुख घटकों के रूप में हक्कानी नेटवर्क और अन्य तालिबान गुट हैं। निस्संदेह, यह तालिबान 1990 के दशक की तुलना में अपनी संरचना में अपेक्षाकृत बड़ा और विविध प्रतीत होता है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में प्रमुख किरदार हैं। फिर हमें इस्लामिक स्टेट खुरासान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे समूहों की उपस्थिति देखने को मिलती हैं, जो डूरंड रेखा के दोनों ओर सक्रिय हैं। इसलिए, मोटे तौर पर, तीन प्रमुख पश्तून-प्रभुत्व वाले सशस्त्र समूह पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से दक्षिण तक पूरे खंड में सक्रिय हैं, और ये सभी समूह दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्रों तथा डूरंड, वह रेखा जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून मुख्य रूप से निवास करते हैं, के विशाल ग्रामीण स्थानों में निहित हैं। इसलिए, यह एक ग्रामीण परिघटना है जिसे अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान के सुरक्षा-राजनीतिक परिदृश्य में देखा जा सकता है।

विगत एक वर्ष के दौरान, नए शासन के तहत धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार चिंता का एक अन्य विषय रहा है। भेदभावपूर्ण व्यवहार, जबरन वसूली, हत्याएं और जबरन विस्थापन फिर से शुरू हो गए हैं। हजारा आबादी के खिलाफ जबरन विस्थापन और प्रणालीगत नरसंहार, लक्षित हिंसा व पंजशीर में 600 ताजिक बंधकों की सामूहिक हत्याओं और मानवता के खिलाफ अपराधों के चश्मदीद गवाहों का हवाला देते हुए कई रिपोर्टें[57] सामने आई हैं।

सत्ता हथियाने के महीनों बाद, तालिबान की अंतरिम कैबिनेट ने सदाचार को बढ़ावा देने एवं बुराई की रोकथाम हेतु एक फियासियो मंत्रालय की स्थापना की (जिसने महिला मामलों के पूर्व मंत्रालय के

सत्ता हथियाने के महीनों बाद, तालिबान की अंतरिम कैबिनेट ने सदाचार को बढ़ावा देने एवं बुराई की रोकथाम हेतु एक फियासियो मंत्रालय की स्थापना की (जिसने महिला मामलों के पूर्व मंत्रालय के परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे बाद में नए शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया था), जिसने देश में मानवाधिकारों, विशेषकर महिलाओं के मानवाधिकारों को लेकर नए सिरे से चिंता पैदा कर दी।

परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे बाद में नए शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया था),

जिसने देश में मानवाधिकारों, विशेषकर महिलाओं के मानवाधिकारों को लेकर नए सिरे से चिंता पैदा कर दी। हाल ही में, उन्होंने अफगानिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग को भी खत्म कर दिया। प्रतिबंधों के लागू होने से तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान में मौजूद जीवंत अफगान मीडिया परिदृश्य पर काफी प्रभाव पड़ा है; मीडिया को नियंत्रित करने के लिए मनमानी गिरफ्तारी, समन, यातना, पत्रकारों को धमकियां और चेतावनियां दी जाती रही हैं। यूएनएएमए ने पत्रकारों से जुड़े 173 मामले सामने आने की बात कही है, जिनमें से 163 को तालिबान शासन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।[58] अफगानों के अधिकारों का सम्मान करने और अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करने वाले लोगों को माफी देने के नए शासन के वादों के बावजूद, तालिबान अपने वादों को लागू करने में काफी हद तक विफल रहा है।

अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में भारी कमी आई है। आज तक, किसी भी महिला को किसी भी उच्च-स्तरीय राजनीतिक पद पर नियुक्त नहीं किया गया है और न ही महिलाओं को राजनीतिक जीवन में कोई सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति है। तालिबान जानबूझकर महिलाओं पर नीतियों से संबंधित सवालों का जवाब देने से बचता है और उन्होंने यह कहते हुए एक सामान्य जवाब दिया है: "वे शरिया कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं"। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बड़े पैमाने पर महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया है। अगर कोई उम्मीद थी कि तालिबान अफगानिस्तान के नागरिक समाज एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए बार-बार की जाने वाली पुकार पर ध्यान देगा, तो महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढंकने के फरमान[59] से यह उम्मीद भी खत्म हो गई है। अफ़गान महिलाओं ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की - काबुल की सड़कों पर उतर कर विरोध किया, यहाँ तक कि तालिबान की हिंसा एवं विरोध पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के बावजूद भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में अफगान महिलाओं की स्थिति को "धीमी मौत" कहा गया है।[60]

अफगान इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज, अफगानिस्तान के निदेशक डॉ. दावूद मोराडियन के अनुसार, 15 अगस्त 2021 को काबुल में जो हुआ उसे सिर्फ एक शब्द - "राजनीतिक हत्या" या

> तालिबान के नेताओं ने इसपर कोई स्पष्टता नहीं दिखाई है कि अफ़ग़ानिस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा या वे राज्य की संरचना किस प्रकार करने की योजना बना रहे हैं।

राजनीतिक व्यवस्था का नरसंहार कहकर वर्णित किया जा सकता है। उनका तर्क है, "यह शासन में बदलाव नहीं था, यह क्रांति नहीं थी, न ही यह तख्तापलट था। उस दिन एक राजनीतिक व्यवस्था की हत्या हुई थी। 16 अगस्त को न केवल अशरफ गनी या राजनीतिक अभिजात वर्ग को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा; सैकड़ों लोगों ने अपनी नौकरी और पहचान खो दी... अगर कोई शख्स 15 अगस्त तक पत्रकार था, अगले ही दिन उसकी पत्रकार की पहचान छिन ली गई थी।' उन्होंने इस

परिघटना को "राजनीतिक हत्या" कहा और तर्क दिया कि अफगानिस्तान ने राज्य का दर्जा खो दिया है, उसके पास कोई राष्ट्रीय सेना नहीं है और वहां देश के लोगों द्वारा समर्थित सरकार नहीं है; यह एक अधिनायकवादी पतन था और इसके कारण हर अफगानी नागरिक का हर पहलू प्रभावित हुआ था।[61] 1990 के दशक के अनुसार, तालिबान (इस्लामी) शरिया की अपनी व्याख्या के आधार पर इस्लामिक राज्य स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। फिर भी, ऐसा लगता है कि तालिबान आंदोलन में इस्लामी व्यवस्था के स्वरूपों के बारे में अलग-अलग विचार हैं। इसके अलावा, अन्य देशों में इस्लामी संविधान, साथ ही पिछले अफगानिस्तान संविधान, बहुत अलग मॉडल के हैं, साथ ही संभावित भविष्य की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। अब तक, तालिबान के नेताओं ने इसपर कोई स्पष्टता नहीं दिखाई है कि अफ़ग़ानिस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा या वे राज्य की संरचना किस प्रकार करने की योजना बना रहे हैं। विगत कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन तालिबान किस तरह के पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली को अपनाएगा (लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) के बारे में सवाल नहीं पूछे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान ने लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा (जिसकी अनुमति उन्होंने सत्ता में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान नहीं दी थी) जैसे कुछ मुद्दों पर अपनी पिछली बयानबाजी की तुलना में नरम पड़ा है, लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि नीतिगत प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन हेतु सुरक्षा, संसाधन और समय की आवश्यकता होती है।

4. अफगानिस्तान के सामने मुख्य चुनौतियां

2021 में अफ़ग़ानिस्तान में जिस तरह से शासन में परिवर्तन हुआ, उससे देश में अनिश्चितता आ गई और उसे जटिल एवं परस्पर संबद्ध दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

<u>गहरा मानवीय एवं आर्थिक संकट</u>

संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय आपात स्थितियों की सूची में रखा है, यह अनुमान लगाते हुए कि 18 मिलियन से अधिक लोगों - लगभग आधी आबादी - को जून और नवंबर 2022 के बीच गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है।[62] डब्ल्यूएचओ (तालिका 1) के अनुसार, 40% कमजोर आबादी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तालिबान के कब्जे

2021 में अफ़ग़ानिस्तान में जिस तरह से शासन में परिवर्तन हुआ, उससे देश में अनिश्चितता आ गई और उसे जटिल एवं परस्पर संबद्ध दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

के पश्चात वाशिंगटन और अन्य देश अफगानिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोकने, अफगान बैंकिंग सेक्टर को अलग-थलग करने और केवल पुरुष तालिबान सरकार के दर्जनों सदस्यों पर लंबे समय से चल रहे प्रतिबंधों को सख्त करने के लिए प्रेरित हुए। देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को आय का नुकसान हुआ और इसने खाद्य सुरक्षा में गिरावट आई है। कोविड-19 की चुनौतियों के अलावा, अफगानिस्तान में सूखे व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने मानवीय संकट की गंभीरता को और बढ़ाया है। तालिबान विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने, फ्रीज किए हुए धन की वापसी और अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए इस आपदा का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगान लोगों को आपातकालीन राहत प्रदान करते हुए उन मांगों को टाल दिया। गैर-सरकारी संगठनों को अभी तक ऐसा कोई भुगतान तंत्र नहीं मिल सका है जिसके ज़रिए वो देश के बाहर से अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन का हस्तांतरण कर सके। वे राहत राशि का इस्तेमाल तालिबान द्वारा अपने लड़ाकों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल करने को लेकर भी सावधानी बरत रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, तालिबान अपने पसंद के लाभार्थियों को ही मानवीय सहायता भेज रहा है।[63]

तालिका 1. प्रमुख आँकड़े: अफगानिस्तान
18.4 मिलियन आबादी को मानवीय सहायता की आवश्यकता है
> पिछले 2 महीनों में विस्थापित हो चुके 300,000 लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है
> 2300 स्वास्थ्य सुविधाओं में से 90% के बंद होने का जोखिम है
> 26 अगस्त 2021 तक कोविड-19 के 153,000 मामले सामने आईं और 7103 मौतें हुई
40% कमजोर आबादी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं
स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन, दिसंबर 2021[64]

पिछले साल से, अफगानिस्तान अपने बैंकिंग क्षेत्र के पतन के कारण गंभीर नकदी संकट का सामना कर रहा है। 2021 के अंत में किए गए विश्व बैंक के निजी क्षेत्र के रैपिड सर्वे से पता चला है कि

अफगानिस्तान अपने बैंकिंग क्षेत्र के पतन के कारण गंभीर नकदी संकट का सामना कर रहा है।

नौकरी छूटने और घटती क्रय शक्ति से उपभोक्ता मांग काफी कम (चित्र 2 और 3) हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने फरवरी में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसका उद्देश्य अफगान लोगों को लाभान्वित करने हेतु मानवीय सहायता के लिए $7 बिलियन का आधा हिस्सा जारी करना था। बाकी तालिबान के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में आतंकवाद से संबंधित मुकदमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तालिबान ने वाशिंगटन से प्रतिबंधों को हटाने और देश के गहराते आर्थिक व मानवीय संकटों से निपटने में तालिबान की मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रोके गए अफगान फंड के "बिना शर्त" $7 बिलियन जारी करने का लगातार आग्रह किया है। हालाँकि

ऐसी रिपोर्टें हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रखे गए धन को जारी करने के लिए प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेदों के कारण इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।[65] संयुक्त राष्ट्र और विदेशी सरकारों ने अफगानिस्तान में लगभग 1 बिलियन डॉलर की मुद्रा निवेश किया है, लेकिन नकदी की कमी बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तालिबान शासन को दरकिनार करते हुए अफगान मुद्रा से डॉलर का व्यापार करने के लिए मानवीय विनिमय सुविधा[66] शुरू की है; हैरानी की बात है कि, तालिबान के अधिकारियों ने इसके कार्यान्वयन का विरोध किया है।

चित्र 2. गतिविधि के क्षेत्र द्वारा उपभोक्ता मांग (उत्तरदाताओं का%)

चित्र 3. रोजगार में औसत % गिरावट

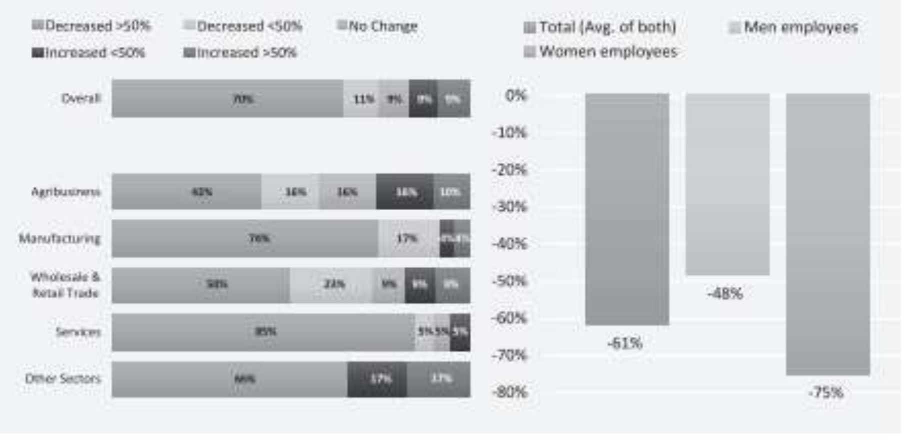

स्रोत: अफगानिस्तान डेवलपमेंट अपडेट, अक्टूबर 2022 (विश्व बैंक)[67]

सुरक्षा चुनौतियां

तालिबान द्वारा बाहरी आतंकवादियों को देश में घुसने न देने के कई बयानों के बावजूद, अल कायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, आईएसकेपी, टीटीपी तथा कई अन्य आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य सेनाओं के हटने ने आतंकवादी समूहों को अच्छा अवसर मिला है। काबुल[68] में एक सुरक्षित ठिकाने पर अमेरिकी ड्रोन के हमले द्वारा अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की लक्षित हत्या केवल इस बात को उजागर करती है कि तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय जिहादियों को शरण देना जारी रखा है जो इस क्षेत्र और उससे आगे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। नई सरकार के सुरक्षा तंत्र में हक्कानी नेटवर्क से जुड़े उग्रवादियों की प्रमुखता सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, भारत इस बात को लेकर चिंतित हो सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान-गठबंधन वाले आतंकवादी संगठनों को संभावित हमलों को अंजाम देने के लिए रसद, भर्ती और योजना हेतु अफगानिस्तान का उपयोग करने की आजादी दी जा सकती है।

पिछले एक साल से, आईएसकेपी, जो बड़े इस्लामिक स्टेट समूह से अफगानिस्तान से संबद्ध है, लगातार हमले कर रहा है तथा नाटो बलों के हटने के बाद से और अधिक घातक हो गया है।

आईएसकेपी का तालिबान के साथ खुले तौर पर विरोधात्मक संबंध, नई सरकार की कमजोरी और अफगानिस्तान के भीतर अपनी भर्ती, धन उगाहने और क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत करने में बुनियादी सामाजिक सेवाओं और व्यस्तताओं को स्थापित करने के अपने संघर्ष का लाभ मिलता है।

आईएसआईएल-केपी ने अफगानिस्तान में काबुल, कुंदुज,[69] कंधार[70] और नांगरहार प्रांतों में कई खूनी हमले किए हैं। समूह ने विशेषतः जातीय अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मस्जिदों को निशाना बनाया है। विद्रोहियों ने उन क्षेत्रों में बमबारी की जहां पहले उनकी उपस्थिति कम थी। आईएसकेपी का तालिबान के साथ खुले तौर पर विरोधात्मक संबंध, नई सरकार की कमजोरी और अफगानिस्तान के भीतर अपनी भर्ती, धन उगाहने और क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत करने में बुनियादी सामाजिक सेवाओं और व्यस्तताओं को स्थापित करने के अपने संघर्ष का लाभ मिलता है। आईएसपीके सेनानियों ने अफगानिस्तान की सीमाओं और क्षेत्र को नियंत्रित करने के तालिबान के दावे को कमजोर करने और अफगान व मध्य एशियाई चरमपंथियों से अधिक भर्ती के प्रयास में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में मिसाइलें लॉन्च की थीं।[71] अमेरिकी सरकार ने अक्टूबर 2021 में अनुमान लगाया था कि आईएसकेपी 6 से 12 महीनों में यूएसए के खिलाफ बाहरी संचालन करने की अपनी क्षमता का पुनर्गठन कर सकता है।[72] लेकिन समूह के खिलाफ तालिबान के तीव्र ऑपरेशन के बाद, आईएसकेपी के हमले 2022 की पहली छमाही में कम हो गए। इसके विपरीत, उत्तर में तालिबान विरोधी हमले, जहां विपक्षी समूह सबसे अधिक सक्रिय हैं, पिछले कुछ महीनों में वृद्धि देखी है, इससे पता चलता है कि ये समूह पहाड़ों में हिमपात रुकने से लाभान्वित हो रहे हैं। अधिकांश विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि एनआरएफ हमलों की संख्या 2022 के वसंत में आईएसकेपी हमलों से अधिक हो गई, जो गर्मियों में बढ़ती रही (चित्र 4 देखें, जो दोनों समूहों द्वारा हमलों की संख्या को दर्शाती है) है। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति अफगानिस्तान के भीतर मौजूदा मानवीय संकट को बदतर बना रही है।

चित्र 4. एनआरएफ और आईएसकेपी से जुड़ी हिंसक घटनाएं।

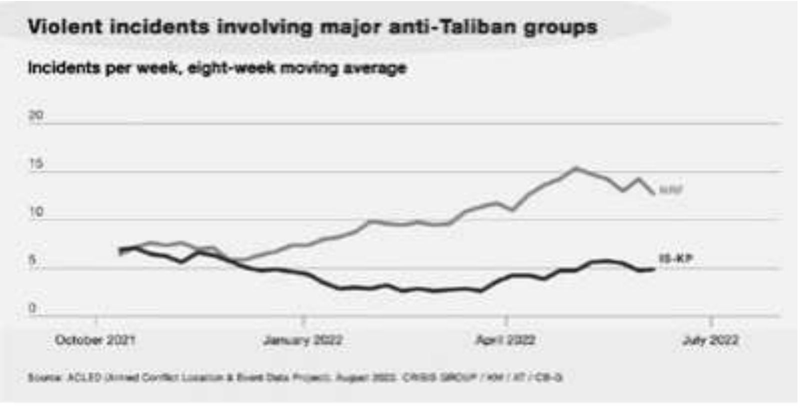

स्रोत: इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप रिपोर्ट, अगस्त 2022[73]

समावेशी राजनीतिक समझौता

इस समूह पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक व्यापक-आधारित राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से देश पर शासन करने का दबाव डाला जा रहा है, जिसमें दीर्घकालिक राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सभी अफगान समूहों का प्रतिनिधित्व किया जाए। तालिबान द्वारा घोषित कैबिनेट "कार्यवाहक" था और समावेशी नहीं है। अधिक "समावेशी, प्रतिनिधि और एकीकृत" होने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दबाव के जवाब में, तालिबान ने कहा कि "हम समावेशिता के लिए तैयार हैं, लेकिन चयनात्मकता हेतु नहीं।"[74] हालांकि, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं देखा गया है। जुलाई 2022 में तालिबान के "उलेमा के महान सम्मेलन" में दुर्लभ उपस्थिति बनाते हुए, जुलाई 2022 में तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुनज़ादा ने अफगानिस्तान के "आंतरिक मामलों" में दुनिया के हस्तक्षेप पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और संकेत दिया कि तालिबान दुनिया के दिशा-निर्देश पर अपने देश को चलाने को लेकर अनिच्छुक है।[75] कई अन्य मुद्दों (विशेषतः यूक्रेन संकट के बाद) पर अपनी नीतियों में बदलाव के बावजूद, न तो चीन और न ही रूस ने अफगानिस्तान पर अपनी नीतियों में बदलाव किया है। पश्चिमी शक्तियों के विपरीत, रूस और चीन ने लैंगिक मुद्दों, मानवाधिकारों के उल्लंघन आदि के बजाय आर्थिक और मानवीय समस्याओं पर यूएनएएमए के जनादेश पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की है, और तालिबान को औपचारिक रूप से अफगानिस्तान का "वास्तविक प्राधिकरण" बताया है। अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए मास्को और बीजिंग तालिबान शासन के साथ गहन जुड़ाव पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वे शासन की मान्यता को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहमति से अलग हों।

5. इतिहास से सबक जो तालिबान शासन-प्रणाली के पक्ष में हो सकते हैं

पिछली सरकारों की तुलना में, तालिबान बहुत कुछ इंगित कर सकता है जो उनके पक्ष में है। वर्तमान में, तालिबान अफगानिस्तान के लगभग पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसका यह एक ही

हालाँकि आज सशस्त्र विरोध की जानकारी है, फिर भी कोई भी सशस्त्र प्रतिरोध बल अब तक देश भर में सभी जातियों के आधार को छूने में कामयाब नहीं हुआ है; नतीजतन, ऐसा "राष्ट्रीय आंदोलन" जो तालिबान का मुकाबला कर सकता है, की काफी हद तक कमी है।

प्राधिकरण द्वारा शासित है। 1990 के दशक में तालिबान शासन का विरोध करने वाले न केवल गुटीय लड़ाके एवं नेता बल्कि बुद्धिजीवी और पेशेवर भी उत्तर में शरण ले सकते थे, क्योंकि यह तालिबान के नियंत्रण में नहीं था। वे कम से कम देश में रह सकते थे। इस बार विपक्ष को संगठित करने का भी समय नहीं था। हालाँकि आज सशस्त्र विरोध की जानकारी है, फिर भी कोई भी सशस्त्र प्रतिरोध बल अब तक देश भर में सभी जातियों के आधार को छूने में कामयाब नहीं हुआ है; नतीजतन, ऐसा "राष्ट्रीय आंदोलन" जो तालिबान का मुकाबला कर सकता है, की काफी हद तक कमी है। अंतर्राष्ट्रीय मदद से अफगानिस्तान के कई प्रतिभाशाली लोगों के हुए पलायन ने देश ऐसे कई अफगानों से वंचित हो गया है जो नागरिक या सैन्य प्रतिरोध में शामिल हो सकते थे या नेतृत्व कर सकते थे।

2001 के बाद, तालिबान पाकिस्तान से मजबूत समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहा है। इसने उन तालिबानी नेताओं को सुरक्षित आश्रय दिया जो आंदोलन को पुनर्गठित व प्रेरित कर सकते थे।

आज, अफगानिस्तान के अधिकांश पड़ोसी नए प्रशासन के साथ जुड़ रहे हैं, और कोई भी क्षेत्रीय देश अभी तक तालिबान के विरोध में कोई सक्रिय भूमिका निभाने में दिलचस्पी नहीं लेता दिख रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा तालिबान का पोषण किया गया था।

पाकिस्तान उग्रवाद शुरू करने की तालिबान की क्षमता का मूल आधार था और उसके बाद लगातार इससे लाभ हासिल किया। आज, अफगानिस्तान के अधिकांश पड़ोसी नए प्रशासन के साथ जुड़ रहे हैं, और कोई भी क्षेत्रीय देश अभी तक तालिबान के विरोध में कोई सक्रिय भूमिका निभाने में दिलचस्पी नहीं लेता दिख रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा तालिबान का पोषण किया गया था। देश के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ताजिकिस्तान, ईरान या तुर्की में आश्रय पा चुके है, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं है कि उन्हें कम से कम खुले तौर पर उन देशों से आंदोलन और संगठित करने की अनुमति दी जा रही है या ऐसा करने के लिए उनका समर्थन किया जा रहा है। फिर भी, इतिहास इस बात की चेतावनी भी देता है कि कैसे, अगर अफगानिस्तान बर्बाद होना शुरू होता है, तो विरोधी गुटों को पड़ोसी का समर्थन संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि 1990 के दशक में हुआ था, भले ही प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पक्षों की संघर्ष में रुचि नहीं थी।

अफगानिस्तान "संकट" और तालिबान की शासन-प्रणाली

दोहा स्थित समूह के राजनीतिक कार्यालय से तालिबान को जोखिम, प्रशिक्षण और राजनीतिक बातचीत और कूटनीति की कला सिखने का अवसर मिला है; नतीजतन, समूह को 1990 के दशक की तुलना में, जब केवल तीन देश उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक वैधता प्राप्त है। अफगानिस्तान में सत्ता में उनकी वापसी से पहले ही, तालिबान प्रतिनिधिमंडलों को वार्ता के लिए विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक राजधानियों में बुलाया जाता था, जिससे विद्रोही समूहों को एक प्रकार का महत्व और वैधता मिलती थी जो पहले कभी नहीं थी। तालिबान के "अंतरिम" कैबिनेट की गैर-समावेशी प्रकृति की आलोचना के बावजूद, तालिबान के साथ राजनयिक जुड़ाव काबुल पर कब्जा करने के तुरंत बाद शुरू हो गया। चूंकि वे देश के नियंत्रण में थे, कई देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ जुड़ने का फैसला किया। कई देशों ने दोहा चैनल के जरिए तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश की है।

तालिबान अपनी सापेक्ष एकता की बात कर सकता है, खासकर जब मुजाहिदीन बनाने वाले गुटों के साथ उसकी तुलना की जाती है, जो 1992 में पीडीपीए की हार से पहले ही आपस में लड़ने लगे थे। हालांकि तालिबान के भीतर गुटीय प्रतिद्वंद्विता की खबरें थीं, समूह अब तक इसे लपेटे में रखने में

दोहा स्थित समूह के राजनीतिक कार्यालय से तालिबान को जोखिम, प्रशिक्षण और राजनीतिक बातचीत और कूटनीति की कला सिखने का अवसर मिला है; नतीजतन, समूह को 1990 के दशक की तुलना में, जब केवल तीन देश उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक वैधता प्राप्त है।

कामयाब रहा है। सरकारी पदों से आंदोलन के भीतर कैडरों और विभिन्न नेटवर्कों को पुरस्कृत करने सहित आंतरिक सामंजस्य को प्राथमिकता देने के तालिबान के फैसले का मतलब एक बहुत ही विशिष्ट प्रशासन है। इसमें जोखिम है कि बेहतर काम कर सकने वाले अनुभवी पेशेवरों के बजाय

तालिबान अपनी सापेक्ष एकता की बात कर सकता है, खासकर जब मुजाहिदीन बनाने वाले गुटों के साथ उसकी तुलना की जाती है, जो 1992 में पीडीपीए की हार से पहले ही आपस में लड़ने लगे थे।

मुल्लाओं को नियुक्त किया जाता है, जिसमें अधिकांश अफगान सरकार को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं और संभावित दाताओं के साथ संबंध तब खतरे में पड़ जाते हैं जब अन्य देश, क्षेत्रीय व आगे दोनों दूर, "समावेशी सरकार" की मांग जारी रखें।

तालिबान में विदेशी धन का विशाल प्रवाह जो देश में आ रहा था - 15 अगस्त तक जो सकल घरेलू

> भारत जैसा देश, जिसका अगस्त 2021 से पहले शासन के साथ कोई औपचारिक जुड़ाव नहीं था और तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से अपनी राजनयिक उपस्थिति हटाने वाले देशों में से एक था, ने अफगानिस्तान को मानवतावादी सहायता भेजने की प्रक्रिया में शासन के साथ जुड़ गया।

उत्पाद के 40% से अधिक है - रातोंरात रुक गया। हार्ड करेंसी की कमी के कारण बैंकिंग क्षेत्र पंगु हो गया है, और देश के विदेशी भंडार को फ्रीज कर दिया गया है और नए प्रशासन की पहुंच से बाहर कर दिया गया। तालिबान या उसके नेताओं पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी प्रतिबंध, अब तालिबान सरकार पर लागू होते हैं और इसलिए ये अफगानिस्तान पर भी लागू होते हैं। फिर भी तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति ने विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को तालिबान के साथ जुड़ने के लिए मजबुर कर दिया है। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए और देश में संकटों को दूर करने के प्रयास किए गए। इनमें से कई विचार-विमर्शों में तालिबान को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक मंच दिया गया। यूएसए ने सितंबर 2022 से सीमित मानवीय छूट शुरू की; साथ ही, 22 दिसंबर को, संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय गतिविधियों और "बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने वाली अन्य गतिविधियों" के लिए छूट लागू की।[76]

भारत जैसा देश, जिसका अगस्त 2021 से पहले शासन के साथ कोई औपचारिक जुड़ाव नहीं था और तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से अपनी राजनयिक उपस्थिति हटाने वाले देशों में से एक था, ने अफगानिस्तान को मानवतावादी सहायता भेजने की प्रक्रिया में शासन के साथ जुड़ गया। विनाशकारी भूकंप और भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री की आवश्यकता ने नई दिल्ली को कुछ कर्मियों को तैनात करने और काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने के लिए मजबुर कर दिया।[77] यह सच है कि बहुत अधिक मानवीय सहायता का वादा किया गया है, फिर भी ये देश की अधिक धन की आवश्यकता की तुलना में ये समुद्र में बूँदें जैसी हैं। किसी भी देश ने अभी तक नई सरकार को मान्यता नहीं दी है, यहां तक कि तालिबान के मुख्य समर्थक पाकिस्तान ने भी नहीं। इसके अलावा, सैन्य जीत के माध्यम से सत्ता हासिल करने के तालिबान के फैसले से अटूट और अनिवार्य रूप से जुड़ी आर्थिक तबाही अभी भी नई सरकार को कमजोर कर सकती है। भूखे लोग शायद ही विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन दुर्लभ संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा एक केन्द्रापसारक बल साबित हो सकती है जो तालिबान की एकता और नेतृत्व करने वाले कमांडरों के नियंत्रण को कमजोर करती है। क्या सीमा चौकियों, ड्रग्स और खदानों से होने वाला राजस्व आगे भी केंद्रीय खजाने में आता रहेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

यह याद रखना जरुरी है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने को अफ़गानों द्वारा अलग तरह से देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर नागरिकों ने, जैसा कि 1990 के दशक में, तालिबान को मुक्तिदाता शक्ति के रूप में देखा था, जिसने हिंसा का अंत किया है, कहीं पर तालिबान को कब्जे की ताकत माना जाता है। शहरी केंद्र, जिसको अमेरिका के नेतृत्व वाले समय में लाभ मिला, तालिबान की जीत को शांति और व्यवस्था लाने वाला नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हताहत हमलों और आईईडी व लक्षित हत्याओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की हत्या का कारण मानते थे। अफ़ग़ानिस्तान के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में भी, कई वर्षों में उग्रवाद से मरने वालों की संख्या अधिक रही है। 2001 में, देश बेहतर दिनों की आशा के साथ अलगाव और अभाव से उभरा।

अमेरिका के 20 साल के हस्तक्षेप के बाद 2021 अफगानिस्तान का संदर्भ बिल्कुल अलग था। जिन लोगों ने महसूस किया कि मूर्खतापूर्ण हिंसा और उग्रवाद का अंत होगा, वे जल्द ही इस घर के

अफ़ग़ानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है वह अभी भी बदतर हो रही है, और दुनिया इस पर कड़ी नज़र रख रही है।

शिकार हो गए कि गिरती अर्थव्यवस्था से उनके और उनके परिवारों पर क्या असर होगा। अलगाव और गरीबी ने एक बार फिर देश को अपनी चपेट में ले लिया है और गरीबी, भुखमरी, आजीविका के अवसरों की कमी और विभिन्न स्तरों पर भेदभाव अफगान लोगों के दुश्मन बन गए हैं। विशेष रूप से काबुल में बार-बार होने वाले हमलों और हत्याओं ने तालिबान की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता पर सवालिया निशान लगा दिया है, शासन या अधिकार तो दूर की बात है।

अफ़ग़ानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है वह अभी भी बदतर हो रही है, और दुनिया इस पर कड़ी नज़र रख रही है। हालांकि यह सच है कि यूक्रेन में संकट के बाद अफगानिस्तान के मुद्दे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए पीछे छूट गए हैं, देश अस्थिर अफगानिस्तान के निहितार्थों से अवगत हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन, महिलाओं के अधिकारों के उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को शरण संबंधी परेशान करने वाली रिपोर्टों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को बढ़ा दिया है, और वे शासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उन चिंताओं पर कार्रवाई करने का उनका इरादा संदिग्ध है। अमेरिकी ड्रोन हमले द्वारा काबुल में अल-कायदा नेता अल-जवाहिरी की हत्या ने साफ कर दिया है कि आशंका गलत नहीं थी।[78]

6. संभावित परिदृश्य: अफगानिस्तान की आगे की राह क्या हो सकती है?

अफगानिस्तान में उभरती स्थिति को देखते हुए, यह आकलन करना मुश्किल है कि देश की स्थिति निकट भविष्य में कैसी होगी; फिर भी, इस शोधपत्र में तीन मध्यम-दीर्घकालिक परिदृश्यों को सामने रखने का प्रयास किया गया है कि अफगानिस्तान की स्थिति यहां से कैसी हो सकती है।

1. **मान्यता के बिना शासन का अस्तित्व:** इस शोधपत्र के पिछले खंड ने उन कारकों पर चर्चा की गई है जो तालिबान शासन के पक्ष में हो सकते हैं और इससे सोच से अधिक समय तक तालिबार शासन बना रह सकता है। अंतरिम कैबिनेट गठन के समय, तालिबान के भीतर गुटबाजी होने का अनुमान था। इसके बाद, अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा करने हेतु काबुल में पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख जनरल फैज़ हमीद की उपस्थिति के संदर्भ में आगे कहा कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेकर कुछ

देश की बिगड़ती आर्थिक और मानवीय स्थिति से इस तर्क को बल मिला कि तालिबान शासन में अफगानिस्तान पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएगा और शासन ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ।

गुटों के बीच असंतोष देखने को मिला है।[79] अगले कुछ महीनों के दौरान, कई मुद्दों पर ऐसी रिपोर्टें आईं, जिन पर अलग-अलग तालिबान गुटों ने अलग-अलग स्थितियाँ रखीं है, जिससे कुछ लोगों को लगा कि शासन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। देश की बिगड़ती आर्थिक और मानवीय स्थिति से इस तर्क को बल मिला कि तालिबान शासन में अफगानिस्तान पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएगा और शासन ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। यह सच है कि वर्तमान में तालिबान में राज्य की वैधता एवं राज्य क्षमता दोनों का अभाव है, जो राज्य चलाने के आवश्यक घटक हैं। हालांकि, अफगानिस्तान में ऐतिहासिक रूप से शायद ही किसी ने देखा हो कि राज्य क्षमता एवं वैधता दोनों को महत्व देता है, इसलिए तालिबान को यहां किसी भी अभूतपूर्व चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और यह संभव है कि वे उनसे वैधता या स्वीकृति को लेकर चिंतित नहीं हैं जिन पर वे शासन कर रहे हैं। हालांकि, वे वास्तव में राज्य को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों प्राप्त करने के लिए बाहरी देशों से मान्यता और वैधता में रुचि रखते हैं। मुद्दों और चुनौतियों के बावजूद, ऐसी संभावना है कि शासन बचा रहेगा। जिस रूप और तरीके से तालिबान अफगानिस्तान पर शासन करेगा, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय, अफगान डायस्पोरा या यहां तक कि अफगानिस्तान में रहने वाले अफगानों के बड़े वर्ग के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है; बहरहाल, फिर भी वे देश पर शासन करना जारी रखेंगे। क्षेत्रीय देशों और वैश्विक शक्तियों के बीच आतंकवाद से निपटने पर शासन के साथ सहयोग करने की इच्छा है। इसलिए यह संभव है कि ज्यादातर देश तालिबान शासन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वे आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता शासन के रास्ते में आने की बहुत संभावना नहीं है, लेकिन पिछले 15 महीनों के अनुभवों को देखते हुए, क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियाँ शासन के साथ जुड़ना जारी रख सकती हैं। अब तक, कुछ मुद्दों पर शासन की अस्पष्टता/स्पष्टता की कमी उनके लाभ को काम कर रही है क्योंकि वे अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्रों में अपने मतभेदों को प्रबंधित करने में उनकी मदद करते हैं; साथ ही, यह अस्पष्टता उन्हें अंतरराष्ट्रीय पक्षों के संबंध में खास बनाए रखने की सुविधा दे रही है।

2. **अफगानिस्तान का विभाजन:** दूसरा संभावित परिदृश्य अफगानिस्तान का बाल्कनीकरण हो सकता है। तालिबान को सबसे अधिक संभावित खतरा आंदोलन से ही है। मध्यम से दीर्घावधि के भविष्य में, तालिबान के विभिन्न गुटों में से ही प्रतिस्पर्धा के विभिन्न द्वीपों का उदय हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में, पहले अमीर-उल-मोमीन मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और अंतरिम कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों को नियंत्रित करने वाले हक्कानी गुट

अब तक, तालिबान के भीतर विभिन्न गुट अपने आंतरिक मतभेदों और प्रतिद्वंद्विता को छिपाने में सक्षम रहे हैं; हालाँकि, भविष्य में, तालिबान के विभिन्न गुटों के बीच ये प्रतियोगिताएँ सामने आ सकती हैं।

के बीच कथित तनाव से तालिबान के भीतर कई खामियां देखी जा सकती हैं।[80] अब तक, तालिबान के भीतर विभिन्न गुट अपने आंतरिक मतभेदों और प्रतिद्वंद्विता को छिपाने में सक्षम रहे हैं; हालाँकि, भविष्य में, तालिबान के विभिन्न गुटों के बीच ये प्रतियोगिताएँ सामने आ सकती हैं। याकूब के तहत तालिबान और सिराजुद्दीन हक्कानी के तहत हक्कानी नेटवर्क के बीच मतभेद भविष्य में सत्तारूढ़ शासन के भीतर अफगानिस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थक गुट बन सकते हैं। हालांकि तालिबान का नेतृत्व पाकिस्तान से आँख बंद करके आदेश लेते रहने के बजाय अपने फैसले खुद कर सकता है, हक्कानी नेटवर्क एक परिवार द्वारा संचालित आतंकवादी कारखाना है जिसे पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा समर्थित और उकसाया जाता है जो जिहादी झुकाव वाले सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के माध्यम से संचालित होता है।[81] आंदोलन के भीतर विभिन्न गुटों के बीच आगे के भविष्य को आकार देने में टीटीपी के लिए तालिबान का समर्थन महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। विभिन्न मुख्यतः पश्तून सशस्त्र समूहों के भीतर की गतिशीलता कैसे आकार लेती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कुछ मौजूदा प्रतिद्वंद्विता पश्तूनों के बीच विभिन्न जनजातियों की राजनीति पर भी आधारित है; यह देखने की जरूरत है कि क्या तालिबान और हक्कानी अंतर-पश्तून गतिकी से शासन को अलग कर सकते हैं। एक निश्चित अवधि में, विभिन्न गुटों के बीच मतभेद और प्रतिद्वंद्विता खुलकर सामने आ सकती है, जिससे हिंसा भड़क सकती है, प्रत्येक समूह अलग-अलग क्षेत्रों को नियंत्रित कर सकता है एवं 1990 के दशक के मुजाहिदीन दिनों की तरह एक-दूसरे से लड़ सकता है। आईएसआईएस-के और तालिबान विरोधी प्रतिरोध बलों (जो देश के उत्तरी भाग में मौजूद हैं और जिनके विस्तार की संभावना है) जैसे समूहों द्वारा ठिकानों का तेजी से विस्तार केवल देश में संघर्ष और हिंसा को बढ़ाएगा। आने वाले समय में पश्चिमी अफगानिस्तान की ओर पीठ करने के साथ, रूस और चीन मुख्य रूप से सीमावर्ती मध्य एशियाई गणराज्यों और झिंजियांग प्रांत को अफगानिस्तान से जिहाद के प्रसार से बचाने में रुचि रखते हैं; अगले बड़े आतंकी हमले तक काबुल दुनिया की नज़र से छिपा रहेगा।

3. **तटस्थ देश के नेतृत्व वाला दृष्टिकोण:** अमेरिका के हटने के पश्चात काबुल हवाई अड्डे पर उतरने वाला पहला विमान कतर एयरवेज का था, जिसमें तालिबान के अनुरोध पर हवाई अड्डे पर परिचालन पुनः शुरू करने हेतु तालिबान की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम थी। इससे पहले, 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका क़तर तक पहुँच गया था ताकि अराजक और हड़बड़ी के बीच हवाई मार्ग से दसियों हज़ार लोगों को निकालने में मदद की जा सके।[82] वाशिंगटन और तालिबान दोनों के साथ अपने संबंधों को देखते हुए, छोटे प्रायद्वीपीय अरब राज्य को अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में विशिष्ट मानते थे। दोहा न केवल वह स्थान

शासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दाम और दंड की नीति के संतुलन को अपनाने की आवश्यकता है, और यह आकलन करना अत्यावश्यक है कि कौन सी नीतियां काम करती हैं और कौन सी नीतियां अफगानों को नियंत्रण में नहीं रख सकती हैं।

था जहां यूएस-तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बल्कि यह वाशिंगटन और तालिबान के बीच एक मध्यस्थ शक्ति भी बन गया, जिसने 2013 से कतर में राजनीतिक कार्यालय - खाड़ी देश के मजबूत संबंधों का एक उदाहरण - बनाए रखा है। काबुल में अमेरिकी राजनयिक मिशन के खत्म होने के बाद, इसे कतर में स्थानांतरित कर दिया गया था, और अफगानिस्तान से संबंधित पश्चिम की अधिकांश व्यस्तताओं को कतर द्वारा सुगम बनाया गया है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में कतर की भागीदारी पिछले कुछ महीनों में कम हो गई है और चीन व रूस जैसे देशों ने भी शासन के साथ अधिक जुड़ाव शुरू कर दिया है, फिर भी कतर जैसे देशों को तटस्थ माना जाता है, जिसे अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। नॉर्वे जनवरी 2022 में तालिबान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच वार्ता की मेजबानी करने में आगे आया। भविष्य में भी इस तरह की वार्ता की उम्मीद की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए तालिबान शासन के साथ जुड़े रहना और सभी गुटों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, भले ही यह आंदोलन के भीतर अधिक रूढ़िवादी तत्व हों या जो सुधार समर्थक हों। शासन को पूरी तरह से बहिष्कृत करने से आंदोलन के भीतर रूढ़िवादी तत्वों को एक ऊपरी मदद मिल जाएगी, जो तब तर्क देंगे कि हालांकि शासन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने का उत्सुक था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें छोड़ दिया। शासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दाम और दंड की नीति के संतुलन को अपनाने की आवश्यकता है, और यह आकलन करना अत्यावश्यक है कि कौन सी नीतियां काम करती हैं और कौन सी नीतियां अफगानों को नियंत्रण में नहीं रख सकती हैं। अफगानिस्तान के दोनों दृष्टिकोणों को समझने के लिए कुछ बातचीत हुई है, और तटस्थ देश भविष्य में दोनों पक्षों के बीच इन आदान-प्रदानों को सुविधाजनक बनाने और समन्वयित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

हालांकि अफगानिस्तान में स्थिति अभी भी उभर रही है, पिछले साल दुनिया ने देखा कि तालिबान की वैचारिक रूपरेखा, जो कि उनके विश्वदृष्टि का मूल आधार है, चाहे लिंग से संबंधित मुद्दों पर हो, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यक समुदायों, शासन के मुद्दे - नागरिक-राज्य जुड़ाव से कैसे निपटें - 1990 के दशक में जिस तरह से थे, वैसे ही बने हुए हैं। हो सकता है कि देश में बड़े पैमाने पर लड़ाई और दिन-प्रतिदिन की असुरक्षा में कमी आई हो (पिछले

हालांकि अफगानिस्तान में स्थिति अभी भी उभर रही है, पिछले साल दुनिया ने देखा कि तालिबान की वैचारिक रूपरेखा, जो कि उनके विश्वदृष्टि का मूल आधार है, चाहे लिंग से संबंधित मुद्दों पर हो, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यक समुदायों, शासन के मुद्दे - नागरिक-राज्य जुड़ाव से कैसे निपटें - 1990 के दशक में जिस तरह से थे, वैसे ही बने हुए हैं।

पिछले कुछ महीनों में तालिबान शासन के प्रति सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरोध बढ़ने के सबूत मिले हैं - उदाहरण के लिए, पहले अमीरात के सभी वर्षों की तुलना में पिछले कुछ महीनों में अधिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खासकर महिलाओं द्वारा।

दशक की तुलना में), लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समूह उन हमलों के लिए जिम्मेदार था, वह आज देश पर शासन कर रहा है। पिछले 12 महीनों में चर्चाएँ काफी हद तक बाहरी शक्तियों से वैधता के सवाल पर केंद्रित रही हैं। हालाँकि, शासन की महत्वपूर्ण चुनौती उन लोगों से वैधता हासिल करने में निहित है जिन पर वे शासन करते हैं। तालिबान शासन से असंतोष - रोजगार के अवसरों की कमी, खाद्य असुरक्षा, बुनियादी अधिकारों की कमी, संक्षिप्त निष्पादन या जबरन गायब होने का खतरा - अंततः ठोस नागरिक प्रतिरोध में तब्दील हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान शासन के प्रति सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरोध बढ़ने के सबूत मिले हैं - उदाहरण के लिए, पहले अमीरात के सभी वर्षों की तुलना में पिछले कुछ महीनों में अधिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खासकर महिलाओं द्वारा। जहां तक सशस्त्र प्रतिरोध का संबंध है, तालिबान द्वारा इसे रोकने के कठोर प्रयास के बावजूद, अफगानिस्तान में सशस्त्र प्रतिरोध जारी है। हालाँकि, अब तक, कोई भी सशस्त्र प्रतिरोध बल देश भर में सभी जातियों के आधार को छूने में कामयाब नहीं हुआ है; नतीजतन, ऐसे "राष्ट्रीय आंदोलन" की जो तालिबान का मुकाबला कर सकता है, वर्तमान में कमी है।

सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों शक्तियों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा। काबुल में ड्रोन हमले में अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की हत्या दर्शाती है कि लगभग एक साल पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भी अमेरिका के पास

> काबुल में ड्रोन हमले में अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की हत्या दर्शाती है कि लगभग एक साल पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भी अमेरिका के पास अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता है।

अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता है। अफगानिस्तान के क्षेत्रीय पड़ोसियों के लिए स्थिति पेचीदा है। आतंकवाद का मुकाबला एक प्रमुख विषय बना हुआ है, और क्षेत्रीय संपर्क एक अन्य चिंता का विषय है। भले ही प्रत्येक पड़ोसी के विशिष्ट हित अलग-अलग हो सकते हैं, फिर भी अफगानिस्तान के आतंकवादी और चरमपंथी समूहों

> यह समझा जा सकता है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण वापस लेने के एक साल बाद भी, किसी भी विदेशी सरकार ने आधिकारिक तौर पर शासन को मान्यता नहीं दी है और निकट भविष्य में इस स्थिति के बदलने की संभावना नहीं है; हालांकि, पिछले वर्ष के बयानों, पहलों एवं जुड़ावों से संकेत मिलता है कि समूह के साथ किसी प्रकार का कामकाजी संबंध होगा।

का पनाहगार बनने पर उनकी साझा चिंताएं हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान एशियाई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चाओं में सुसंगत विषय बना रहेगा। यह समझा जा सकता है कि

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण वापस लेने के एक साल बाद भी, किसी भी विदेशी सरकार ने आधिकारिक तौर पर शासन को मान्यता नहीं दी है और निकट भविष्य में इस स्थिति के बदलने की संभावना नहीं है; हालांकि, पिछले वर्ष के बयानों, पहलों एवं जुड़ावों से संकेत मिलता है कि समूह के साथ किसी प्रकार का कामकाजी संबंध होगा। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अफगानिस्तान से जुड़े रहना और अफगान लोगों को न छोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि तालिबान के साथ उनके जुड़ाव से शासन मजबूत न हो जाए। आने वाला समय महत्वपूर्ण रहने वाला है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सावधानी से कदम रखना होगा। तालिबान ने आतंकवाद को सफलतापूर्वक चलाने की अपनी क्षमता साबित कर दी है। अब, उनके सामने देश चलाने का उससे कहीं अधिक जटिल कार्य है।

1 "Will There Be Women in the Taliban's New Government?" *BBC News*, September 1, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=CMgr7nkFLjo (Accessed April 12, 2022).

2 Marwan Bishara. "What's Next for the US, the Taliban and Afghanistan?" Al Jazeera, August 19. 2021. https://www.aljazeera.com/opinions/2021/8/19/whats-next-for-the-us-taliban-and-afghanistan (Accessed 12.04.2022).

3 Larry P. Goodson. *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics and the Rise of the Taleban* (Seattle and London: University of Washington Press, 2001), p. 12.

4 Yakub Ibrahimi. "State Formation in Afghanistan: A Theoretical and Political History," *Central Asian Survey*, vol. 38 (2018), pp. 172-174.

5 Ibrahimi, Op.cit.

6 S. K. Lambah. "The Durand Line." *Indian Foreign Affairs Journal,* vol. 7, no. 1 (2021), pp. 42-60. https://www.jstor.org/stable/45341803

7 Ibid.

8 Ibid.

9 F. R. Farid. *The Modernization of Afghanistan*, cited in *State Revolution and Superpowers in Afghanistan* (New York, London: Praeger, 1990).

10 Ludwig W. Adamec. *Afghanistan's Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century* (University of Arizona Press, 1975), pp. 177-178.

11 Hafizullah Emadi. *State Revolution and Superpowers in Afghanistan* (New York, London: Praeger, 1990), p. 7.

12 Ibid.

13 Raja Anwar. *The Tragedy of Afghanistan: A First Hand Account* (London and New York: Verso, 1988).

14 Arpita Basu Roy. *Contemporary Afghanistan: Confiict and Peace Building* (Har-ananad Publications, 2010).

15 David Seddon. "Imperial Designs: A Deep History of Afghanistan," *Critical Asian Studies,* vol. 25, no. 2 (2003), p. 191.

16 Mohammad Yousuf and Mark Adkin. *The Bear Trap: Afghanistan's Untold Story* (Lahore: Jang Publishers, 1992).

17 William Maley. *The Afghanistan Wars* (Hampshire and New York: Palgrave Macmillam, 2002), p. 153.

18 Oliver Roy. *Islam and Resistance in Afghanistan* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 213.

19 Lindsay Maizland. “The Taliban in Afghanistan,” Council of Foreign Relations. https://www.cfr.org/ backgrounder/taliban-afghanistan (Accessed 12.04.2022)

20 Ibid

21 Hillary Clinton. “Remarks at the Launch of the Asia Society’s Series of Richard C. Holbrooke Memorial Addresses,” speech delivered at Asia Society, New York, February 18, 2011, 2009-2017. https://2009-2017. state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/02/156815.htm

22 Elisabeth Bumiller and Jane Perlez. “Pakistan’s Spy Agency Is Tied to Attack on U.S. Embassy,” The New York Times, September 22, 2011. www.nytimes.com/2011/09/23/world/asia/mullen-asserts-pakistani- role-in-attack-on-us-embassy.html

23 “Snakes in Your Backyard Won't Bite only Neighbours: Hillary to Pak,” NDTV, October 21, 2011. https:// www.ndtv.com/world-news/snakes-in-your-backyard-wont-bite-only-neighbours-hillary-to-pak-573412 (Accessed 12.05.2022).

24 “US Forces-Afghanistan and Resolute Support Transition of Authority Ceremony,” U.S. Central Command, July 12, 2021. https://www.centcom.mil/MEDIA/Transcripts/Article/2691935/us-forces- afghanistan-and-resolute-support-transition-of-authority-ceremony-jul/ (Accessed 12.05.2022).

25 “Biden Must Decide on US Troops in Afghanistan as Deadline Looms,” Al Jazeera, February 26, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/2/26/at-pivotal-moment-in-afghanistan-war-biden-weighs-a- dilemma (Accessed 13.05.2022).

26 “‘Nothing Is Agreed until Everything Is Agreed’: US Envoy on ‘Progress’ of US-Taliban Talks,” Dawn, January 26, 2019. www.dawn.com/news/1459928 (Accessed 13.05.2022).

27 US Department of State. “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan Which Is Not Recognized by the United States as a State and Is Known as the Taliban and the United States of America,” February 29, 2020. www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/ Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf (Accessed 13.05.2022).

28 “The Taliban Commander Who Led Attack on Afghan City Was Released from Prison Last Year, Official Says,” The Wall Street Journal, August 3, 2021. https://www.wsj.com/articles/taliban-commander- who-led-attack-on-afghan-city-was-released-from-prison-last-year-officials-say-11628010527 (Accessed 12.05.2022).

29 Rakesh Sood. “Distant Dream of Peace after US Exit, What’s next for Afghanistan?” Global Asia, September 2021. https://www.globalasia.org/v16no3/feature/distant-dreams-of-peace-after-the-us- exit-whats-next-for-afghanistan_rakesh-sood (Accessed 12.05.2022).

30 “Joe Biden Explains US Troops Withdrawal from Afghanistan,” CNN, April 15, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=un1CcbrkuZ0 (Accessed 27.10.21).

31 Rory Stewart. “Biden Afghanistan Withdrawal Marks the End of Liberal Interventionism: Rory Stewart Interview,” *The New Statesman*. https://www.youtube.com/watch?v=EX4H_GxTdBA&ab_ channel=TheNewStatesman (Accessed 12.05.2022).

32 “NATO Allies Decide to Start Withdrawal of Forces from Afghanistan,” North Atlantic Treaty Organization, April 15, 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183086.htm (Accessed 12.05.2022).

33 “US Left Baghram Airbase, without Notice,” The Hindu, July 6, 2021. https://www.thehindu.com/news/ international/us-left-afghan-airbase-without-notice/article35178577.ece (Accessed 12.05.2022).

34 “US Left Bagram Airbase at Night with no Notice, Afghan Commander Says,” BBC, July 6, 2021. https:// www.bbc.com/news/world-asia-57682290 (Accessed 27.10.21).

35 Hamdullah Mohib (Former National Security Advisor, Islamic Republic of Afghanistan) in an interview titled “Face the Nation,” December 19, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=q5t8Khew0O4&ab_ channel=FacetheNation (Accessed 1.8.2022).

36 “Amarkhil Discussed Collapse of Former Govt,” *Tolo News Youtube*, September 6, 2021.https://www.youtube.com/ watch?v=zWt1RtTxeFc&t=1025s (Accessed on 12.05.2022).

37 Anthony H. Cordesman, “The Reasons for the Collapse of Afghan Forces,” Center for Strategic International Studies, August 17, 2021. Available at: https://www.csis.org/analysis/reasons-collapse- afghan-forces (Accessed ob 12,5,22)

38 Rakesh Sood, “What Went Wrong in Afghanistan?” Observer Research Foundation, August 31, 2021.

https://www.orfonline.org/research/what-went-wrong-in-afghanistan/ (Accessed 17.05.2022).

39 Rakesh Sood, "Afghanistan: The Sum and Substance of the US-Taliban Deal," Italian Institute for International Political Studies, March 6, 2020. https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/ afghanistan-sum-and-substance-us-taliban-deal-25340 (Accessed 28.05.2022).

40 Antonio Giustozzi. Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan (London: Hurst, 2007), p. 16.

41 One example was appointments by the new defence minister, General Qasim Fahim, leader of the Shura-ye Nazar network within Jamiat-e Islami which had captured Kabul (thereby gaining the ministries of defence, interior and foreign affairs and the NDS). In February 2002, he appointed 38 generals as the new general staff; 37 were his co-ethnic Tajiks and 35 were with Shura-ye Nazar. Of the 100 generals he appointed in total, Giustozzi wrote, 90 belonged to Shura-ye Nazar.

42 Antonio Giustozzi. *Empires of Mud: War and Warlords in Afghanistan* (London, UK: Hurst & Company, 2009). pp. 88-89.

43 S. Yakub Ibrahimi. "Afghanistan's Political Development Dilemma: The Centrist State Versus Centrifugal Society," *Journal of South Asian Development,* vol. 14, no. 1 (2009).

44 David Lyon. The Long War: The Inside Story of America and Afghanistan since 9/11 (New York: St Martin Press, 2021), p. 9.

45 Ibid.

46 "Taliban Enters Afghan Presidential Palace after Ghani Flees," *Al Jazeera*, August 15, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/15/taliban-continues-advances-captures-key-city-of-jalalabad (Accessed 2.8.2022).

47 "Afghan President Ashraf Ghani Flees Country 'to Avoid Bloodshed' as Taliban Enter Kabul," Independent, August 15, 2021.https://www.independent.co.uk/asia/central-asia/afghanistan-taliban- ashraf-ghani-flee-b1902917.html (Accessed 2.8.2022).

48 "Taliban Says Afghanistan War over as President Flees: Live," Al Jazeera, August 16, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/16/taliban-says-afghanistan-war-over-as-president-diplomats-flee (Accessed 2.8.2022).

49 "Deadly Protest in Jalalabad against Removal of Afghan Flag," Al Jazeera, August 20, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/18/at-least-two-killed-by-shots-fired-at-flag-protest-in-afghanistan (Accessed 3.8.2022).

50 Masood Farivar, "Afghan 'Fighting Season' Ushers in New Anti-Taliban Groups," VOA, April 27, 2022. https://www.voanews.com/a/afghan-fighting-season-ushers-in-new-anti-taliban-groups/6542148. html (Accessed 3.8.2022).

51 "Challenges to the Taliban Rule and Potential Impact for Region," Washington Institute, February 9, 2022. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/challenges-taliban-rule-and-potential- impacts-region (Accessed 10.8.2022).

52 "Yaqoob and Haqqani Factions Fight over Taliban Government," The Hindustan Times, September 1, 2021. https://www.hindustantimes.com/world-news/yaqoob-and-haqqani-factions-fight-over-taliban- government-101630474732128.html (Accessed 10.8.2022).

53 "The Taliban Announces New Government in Afghanistan," Al Jazeera, September 7, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/9/7/taliban-announce-acting-ministers-of-new-government (Accessed 3.8.2022).

54 "Taliban Expand Interim Cabinet, 27 New Members Named," Deccan Chronicle, November 23, 2021. https://www.deccanchronicle.com/world/middle-east/231121/taliban-expand-interim-cabinet- 27-new-members-named.html

55 "Taliban Declares Complete Amnesty across Afghanistan," The Economic Times, August 18, 2021. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/taliban-declares-complete- amnesty-across-afghanistan-says-everyone-is-forgiven/articleshow/85418061.cms?from=mdr (Accessed 3.8.2022).

56 "Human Rights in Afghanistan 15 August 2021-15 June 2022," UNAMA, July 2022. https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_human_rights_in_afghanistan_report_-_june_2022_ english.pdf (Accessed 3.8.2022).

57 Ibid

58 Ibid

59 "How the Taliban Are 'Eliminating Women' in Afghanistan," DW, May 9, 2022. https://www.dw.com/en/how-the-taliban-are-eliminating-women-in-

afghanistan/a-61736998 (Accessed 1.8.2022).

60 "Afghanistan: Death in Slow Motion: Women and Girls under Taliban Rule," Amnesty International, 27 July 2022. https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/5685/2022/en/ (Accessed 3.8.2022).

61 Dr. Davood Moradian, Director of the Afghan Institute for Strategic Studies, Afghanistan, speaking at Sussex University, UK, November 25, 2021. Available at: https://www.youtube.com/ watch?v=w5dOJNx6hY8&t=1076s (Accessed 1.8.2022).

62 "Taliban Tout Governance Gains, Urge US to Release Afghan Assets," Voice of America, July 26, 2022. https://www.voanews.com/a/taliban-tout-governance-gains-urge-us-to-release-afghan- assets/6674199.html (Accessed 5.8.2022).

63 "U.N. Says Taliban Interfering with Aid, Resisting Cash Plan," Reuters, June 24, 2022. https://www. reuters.com/world/asia-pacific/un-says-taliban-interfering-with-aid-resisting-cash-plan-2022-06-23/ (Accessed 1.8.2022).

64 "WHO Afghanistan Emergency Plan: Meeting the Health Needs of Afghanistan's Crisis-Affected Populations," World Health Organization, Sep-Dec 2021. https://www.who.int/publications/m/item/ who-afghanistan-emergency-plan-meeting-the-health-needs-of-afghanistan-s-crisis-affected- populations

65 "US and Taliban Exchange Proposals for Release of Funds: Report," Al Jazeera, July 27, 2022. https:// www.aljazeera.com/economy/2022/7/26/us-and-taliban-exchange-proposals-for-release-of-funds- report (Accessed 5.8.2022).

66 "U.N. Aims to Launch New Afghanistan Cash Route in February: U.N. Note," Reuters, February 11, 2022. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-un-aims-launch-new-afghanistan-cash-route- february-un-note-2022-02-10/ (Accessed 1.8.2022).

67 "Afghanistan Development Update," October 2022. World Bank Report. https://thedocs.worldbank.org/ en/doc/d7d49962c0c44fd6bb9ba3bfe1b6de1f-0310062022/original/Afghanistan-Development-Update- October-2022.pdf (Accessed 31.10.22).

68 "Al-Qaeda Leader Ayman Al-Zawahiri Killed in US Drone Strike," Al Jazeera, August 1, 2022. https:// www.aljazeera.com/news/2022/8/1/al-qaedas-ayman-al-zawahiri-killed-in-us-drone-strike-reports (Accessed 10.8.2022).

69 "Afghanistan: Dozens Killed in Suicide Bombing at Kunduz Mosque," Al Jazeera, October 8, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/10/8/blast-hits-a-mosque-in-afghanistans-kunduz-during- friday-prayers (Accessed 10.8.2022).

70 "Afghanistan: Suicide Attack Hits Kandahar Mosque during Prayers," BBC News, October 16, 2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-58925863 (Accessed 10.8.2022).

71 Richard Weitz. "Afghanistan Adrift One Year after the Taliban Takeover," Middle Eastern Institute, August 9, 2022. https://www.mei.edu/publications/afghanistan-adrift-one-year-after-taliban-takeover (Accessed 1.8.2022).

72 "Nonstate Threats in the Taliban's Afghanistan," Brookings Institute, February 1, 2022. https://www. brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/nonstate-threats-in-the-talibans-afghanistan/ (Accessed 10.8.2022).

73 "Afghanistan's Security Challenges under the Taliban," International Crisis Group Report, August 2022. https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-security-challenges-under- taliban (Accessed 31.10.22).

74 "Ready for Inclusivity, Not Selectivity," Al Jazeera, October 9, 2021. https://www.aljazeera.com/ news/2021/10/9/taliban-ready-for-inclusivity-not-selectivity-ahead-of-talks#:~:text=The%20 Taliban's%20%E2%80%9CIslamic%20emirate%E2%80%9D%20is,for%20an%20inclusive%20Afghan%20 government (Accessed 10.8.2022).

75 "Taliban Supreme Leader Addresses Major Gathering in Kabul," Al Jazeera, July 1, 2022. https://www. aljazeera.com/news/2022/7/1/taliban-supreme-leader-addresses-gathering (Accessed 10.8.2022).

76 "Security Council Paves Way for Aid to Reach Desperate Afghans," UNSC Press Release, December 21, 2022. https://news.un.org/en/story/2021/12/1108642 (Accessed 1.8.2022).

77 "Earthquake Relief Assistance for the People of Afghanistan," Ministry of External Affairs, GOI, Press Release, June 24, 2022. https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35440/Earthquake_Relief_ Assistance_for_the_people_of_Afghanistan

(Accessed 7.7.22).

78 "How the C.I.A. Tracked the Leader of Al Qaeda," New York Times, August 2, 2022. https://www.nytimes.com/2022/08/02/us/politics/cia-qaeda-al-zawahri.html?fbclid=IwAR24rRAujP_KHO51wF8Th1DDO2ayC2HDq7aZT8gj28ShS0lCCA4zxUB-c94 (Accessed 7.7.22).

79 "Pak ISI Chief Faiz Hameed Meets Former Afghan PM in Kabul, Discusses Formation of Coalition Govt," *India Today*, September 5, 2021. https://www.indiatoday.in/world/story/pakistan-faiz-hameed-meets- gulbuddin-hekmatyar-afghanistan-govt-1849474-2021-09-05

80 "Yaqoob and Haqqani Factions Fight over Taliban Government," The Hindu, September 1, 2021. https://www.hindustantimes.com/world-news/yaqoob-and-haqqani-factions-fight-over-taliban-government-101630474732128.html

81 Ibid.

82 Anwesha Ghosh. "Qatar's Emergence as a Key Player in Afghanistan," ICWA Viewpoint.

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, भारत दूरभाष. : +91-11-23317242,
फैक्स: +91-11-23322710

www.icwa.in